लखनऊ

बुधवार 14 जनवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 145

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार न दें।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

संक्षेप

पश्चिम बंगाल में मिले 2 मामले; नड्डा ने ममता बनर्जी को किया फोन; हेल्पलाइन नंबर जारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो संभावित मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक अस्पताल में कार्यरत दो नर्सों में निपाह संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। मामलों के सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली है। राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। फिलहाल दोनों संक्रमित नर्सों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों नर्स बारासात के एक ही अस्पताल में काम करती हैं और उनके निपाह वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। उनके नमूने जांच के लिए कल्याणी एम्स भेजे गए हैं और शुरुआती रिपोर्ट में निपाह संक्रमण के संकेत मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार, महिला नर्स नदिया जिले की रहने वाली है, जबकि पुरुष नर्स पूर्व बर्धमान जिले के कटवा क्षेत्र से है। दोनों को उसी अस्पताल में एक अलग वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां वे कार्यरत हैं, और उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि महिला नर्स हाल ही में अपने गृहनगर कटवा से लौटी थी, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। 31 दिसंबर को उसे पहले एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर बर्दवान मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

मोदी जी के विकसित भारत निर्माण के सारथी युवाशक्ति : अनुराग सिंह ठाकुर

देहरादून। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में हजारों युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनसे अपनी ऊर्जा राष्ट्रनिर्माण में लगाने का आह्वान किया। हरिद्वार में आयोजित इस राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष श्री आशीष गौतम, देवप्रयाग विधायक श्री विनोद कंडारी व पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी की गरिमायी उपस्थिति रही। युवाओं को संबोधित करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा विश्व पटल पर भारतीयता, सनातन संस्कृति व हमारे समृद्ध वैचारिक-सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित करने वाले, सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रतीक, असंख्य युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सादर नमन व राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। युवा किसी भी समाज का आधार और भविष्य होते हैं। उनकी ऊर्जा, उत्साह, और नए विचार किसी भी देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को जागरूक और जिम्मेदार बनने का संदेश दिया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चे आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम और सही दिशा से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा आज भारत जहाँ खड़ा है।

डॉग लवर्स की जिम्मेदारी होगी तय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कुत्तों के काटने पर देना होगा भारी मुआवजा

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले पांच वर्षों में आवारा कुत्तों से संबंधित नियमों के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की और मंगलवार को कहा कि वह कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए राज्यों को ''भारी मुआवजा'' देने का आदेश देगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए कुत्ता प्रेमियों और उन्हें खाना खिलाने वालों को भी 'जिम्मेदार' और 'जवाबदेह' ठहराया जाएगा।

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, ''कुत्तों के काटने से बच्चों या बुजुर्गों की मृत्यु या चोट के हर मामले के लिए हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा देने की मांग करेंगे क्योंकि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ नहीं किया है। साथ ही, इन आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो आप उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते इधर-उधर क्यों घूमते हैं, लोगों को काटते हैं और डराते हैं?'' न्यायमूर्ति मेहता ने न्यायमूर्ति नाथ के विचारों से सहमति जताते हुए कहा, ''जब कुत्ते नौ साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? वह संगठन जो उन्हें खाना खिला रहा है? आप चाहते हैं कि हम इस समस्या से आंखें मूंद लें।'' उच्चतम न्यालय सात नवंबर, 2025 के अपने उस आदेश में संशोधन के अनुरोध वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों और सड़कों से इन आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया गया था।

प्रगति पोर्टल से बदली यूपी की तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी बोले– इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बने नंबर वन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रगति (सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन) केवल बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि नए भारत की परिणामोन्मुखी कार्य संस्कृति का सशक्त प्रतीक है। एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित शासन मॉडल को प्रतिबिंबित करती है, जो उद्देश्य, प्रौद्योगिकी और जवाबदेही पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति ने यह साबित कर दिया है कि जब उद्देश्य, प्रौद्योगिकी और जवाबदेही एक साथ आते हैं, तो ठोस परिणाम स्वतः ही सुनिश्चित हो जाते हैं। डिजिटल शासन और सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए, इस मंच ने अंतर-मंत्रालयी और अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से जटिल मुद्दों के समय पर समाधान को संभव बनाया है।

मुख्यमंत्री योगी ने इसकी उत्पत्ति का जिक्र करते हुए बताया कि यह मॉडल 2003 में गुजरात में SWAGAT (State Wide Attention on Grievances by Application of Technology) के रूप में शुरू हुआ था और 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर के प्रगति मंच में विकसित हुआ। राष्ट्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रगति ने देशभर में 86 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को गति देने में मदद की है। उठाए गए 3,162 प्रमुख मुद्दों में से 2,958 का समाधान हो चुका है, जो शासन प्रणाली की विश्वसनीयता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रगति योजना ने राज्य को भारत के अग्रणी अवसंरचना विकास केंद्रों में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रगति के तहत निरंतर निगरानी के कारण एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, हवाईअड्डे, रैपिड रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और रोपवे से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा अवसंरचना पोर्टफोलियो है, जिसमें 10.48 लाख करोड़ रुपये की 330 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 2.37 लाख करोड़ रुपये की 128 परियोजनाएं (39 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं और चालू हो चुकी हैं, जबकि 8.11 लाख करोड़ रुपये की 202 परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रगति पर हैं।

मनरेगा बचाओ संग्राम: कांग्रेस ने लोगों से जुड़ने की अपील की, जयराम बोले-

सरकार ने योजना पर चलाया बुलडोजर

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर में बीते कुछ दिनों से 'मनरेगा' योजना के नाम को लेकर खूब चर्चा चल रही है। इसका बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को हटाकर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना लाना है। इसके बाद से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सरकार ने इस योजना पर बुलडोजर चला दिया है, जबकि यह योजना देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों की रोजी-रोटी का सहारा है। बता दें कि इस योजना के विरोध में कांग्रेस ने बीते 10 जनवरी को 'मनरेगा बचाव संग्राम' शुरू किया था। ऐसे में अब

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि यह अभियान देश की करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा और इसमें करोड़ों लोग जुड़ेंगे। उनका कहना है कि यह आंदोलन लोगों के काम के अधिकार, मजदूरी के अधिकार और जवाबदेही को वापस दिलाने के लिए है। इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए कांग्रेस ने एक समन्वय समिति बनाई है। इसके संयोजक अजय माकन हैं, जबकि जयराम रमेश, संदीप दीक्षित और प्रियंक खरगे जैसे वरिष्ठ नेता इसके सदस्य हैं। कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ संग्राम' 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई ग्रामीण गरीबों के हक और सम्मान के लिए है और इसे देशभर में जन आंदोलन बनाया जाएगा। इस संग्राम को लेकर कांग्रेस ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़ें। इसके लिए पार्टी ने एक वेबसाइट भी शुरू की है, जहां लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी जाने वाली याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कांग्रेस की याचिका में कहा गया है कि मनरेगा एक संवैधानिक अधिकार है और इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी की प्रमुख मांगें है कि इस योजना में काम की गारंटी को पूरी तरह बहाल किया जाए।

भारत के खिलाफ नहीं... बांग्लादेश की सरकार से लेकर सेना तक पर आर्मी चीफ ने स्पष्ट की स्थिति

नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश की स्थिति पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सबसे पहले, हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में किस तरह की सरकार है। अगर यह एक अंतरिम सरकार है, तो हमें यह देखना होगा कि वह जो कदम उठा रही है, वे अगले 4-5 सालों के लिए हैं या सिर्फ़ अगले 4-5 महीनों के लिए।

उन्होंने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत है या नहीं। दूसरा, आज की तारीख में तीनों सेनाओं ने अपने कम्युनिकेशन चैनल पूरी तरह से खुले रखे हैं। भारतीय सेना के पास कम्युनिकेशन के कई चैनल खुले हैं।

दूसरे चैनलों के जरिए हम संपर्क

में हैं

भारतीय सेना प्रमुख ने कहा कि मैं वहां के चीफ के साथ रेगुलर संपर्क में हूं। इसी तरह, हम अपने दूसरे चैनलों के ज़रिए भी संपर्क में हैं। हमने वहां एक डेलीगेशन भेजा था, जिसने ज़मीनी स्तर पर सभी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इसी तरह, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने भी बात की है।

उन्होंने कहा कि मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई गलतफहमी या गलत कम्युनिकेशन न हो। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि, आज की तारीख में, तीनों सेनाओं द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वे किसी भी तरह से भारत के खिलाफ नहीं हैं। जहां तक क्षमता विकास की बात है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भारत भी ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा दूसरे देश भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारी तैयारी की बात है, हम वहां की स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं।

बांग्लादेश से सैन्य संबंध पहले जैसे हैं

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बांग्लादेश की सेना जो भी कर रही है, वह भारत के खिलाफ नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य संबंध पहले जैसे ही हैं। हमारे अधिकारी बांग्लादेश के सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं और उनके अधिकारी यहां प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं।

बिहार में बुजुर्गों को अब घर पर मिलेगी जमीन– फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा : नीतीश कुमार

पटना, एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घर पर ही जमीन या फ्लैट की निबंधन (रजिस्ट्री) सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया। यह सुविधा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा संचालित चलंत निबंधन इकाई (मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट) के माध्यम से निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएगी, जिसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह नयी व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि कई बार यह देखा गया है कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को

जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर उन्हें सहूलियत देने और अनावश्यक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को कई बार संबंधित भूमि की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसे ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री से पूर्व भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।

इसके तहत आवेदकों के अनुरोध पर निबंधन विभाग अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध कराएगा। इससे आवेदकों को जमीन के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नयी सरकार के गठन के बाद 'सात निश्चय-3' कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है।

'सात निश्चय-3' के अंतर्गत सातवां निश्चय 'सबका सम्मान-जीवन आसान' (ईज ऑफ लिविंग) है, जिसका मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और अधिक सरल बनाना है। इसी दिशा में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।

10 मिनट डिलीवरी पर सरकार की 'नो', ब्लिंकइट, ज़ेप्टो को सख्त निर्देश, अब सेफ्टी फर्स्ट!

नई दिल्ली, एजेंसी। डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद, क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकइट ने अपने सभी ब्रांड प्लेटफॉर्म से '10 मिनट में डिलीवरी' का दावा हटा दिया है। इस मुद्दे पर मांडविया ने ब्लिंकइट, ज़ेप्टो, स्विगी और ज़ोमैटो के अधिकारियों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कंपनियों को डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा के हित में सख्त डिलीवरी समय सीमा को समाप्त करने की सलाह दी। मंत्री ने जोर दिया कि आक्रामक समयसीमा डिलीवरी पार्टनर्स पर अनावश्यक दबाव डाल सकती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा सकती है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वे अपने ब्रांड

विज्ञापनों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी डिलीवरी समय संबंधी प्रतिबद्धताओं को हटा देंगे। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हुए गिग वर्कर्स की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। यह घटनाक्रम त्वरित वाणिज्य मॉडलों और वितरण कर्मियों पर उनके प्रभाव की बढ़ती जांच के बीच आया है, जिसमें सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि तेज डिलीवरी के लिए श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। यह कदम दिसंबर के अंत में विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर डिलीवरी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़तालों के कुछ हफ्तों बाद आया है, जिसमें कामकाजी परिस्थितियों, डिलीवरी के दबाव और सामाजिक सुरक्षा की कमी से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। सूत्रों के अनुसार, ब्लिंकइट अपने सभी ब्रांड संदेशों से '10 मिनट में डिलीवरी' का जिक्र हटा देगा। इसमें विज्ञापन, प्रचार अभियान और सोशल मीडिया संचार शामिल हैं।

असम में 'Miya Politics' पर घमासान, मुख्यमंत्री हिमंता सरमा बोले– कांग्रेस बदल रही है डेमोग्राफी

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऊपरी असम के प्रमुख जिलों की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने शिवसागर और तिनसुकिया को धुबरी में बदलने की हालिया टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ (एएमएसयू) के पूर्व अध्यक्ष रेजाउल करीम सरकार ने शिवसागर को धुबरी, बराक घाटी को शिवसागर और तिनसुकिया को धुबरी में बदलने की बात कही थी। उनका दावा था कि ऐसे बदलाव असम को आगे ले जाने में सहायक होंगे।

इस टिप्पणी पर तत्काल तीखी प्रतिक्रिया हुई, खासकर ऊपरी असम में। शिवसागर को ऐतिहासिक रूप से अहोमों का गढ़ माना जाता है, जबकि

धुबरी को व्यापक रूप से बंगाली मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। सरकार ने कहा, 'हम भय में जी रहे हैं,' और आगे कहा कि वह गौरव गोगोई के साथ 'सेनापति' (कमांडर) के रूप में मजबूती से खड़े रहेंगे और असम से हिमंता बिस्वा सरमा को बाहर निकालकर इस चिंता को समाप्त करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें असम और उसके समाज एवं संस्कृति को बचाना है। मुझे विश्वास है कि मैं असम के सभी समुदायों और अपने पिछड़े समुदाय को एक मंच पर लाऊंगा... और एक-दूसरे के सहयोग से हम असम को आगे ले जाएंगे।

मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने कहा कि ये टिप्पणियां प्रमुख जिलों की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के पार्टी के इरादे की खुली घोषणा के समान हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी पर असम के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को खतरे में डालने वाले एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

यह तमिल संस्कृति पर हमला, आवाज दबाने की कोशिश– विजय की फिल्म 'जना नायकन' की रिलीज में देरी पर बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु में एक फिल्म की रिलीज को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा विजय अभिनीत फिल्म 'जना नायकन' को "रोकने की कोशिश" तमिल संस्कृति पर हमला है, और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "तमिल लोगों की आवाज को दबाने" में कभी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस नेता की ओर से यह टिप्पणी तमिल फिल्म 'जना नायकन' के प्रोड्यूसर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती देने के एक दिन बाद आई है, जिसने फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (Central Board of Film Certification, CBFC) से मंजूरी देने के सिंगल जज के निर्देश

पर रोक लगा दी थी। फिल्म रिलीज होने में हो रही देरी पर राहुल से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी केंद्र की आलोचना कर चुके हैं।

डिविजन बेंच ने लगाई सिंगल बेंच के फैसले पर रोक

पिछले हफ्ते 9 जनवरी को, मद्रास हाई कोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें CBFC को 'जना नायकन' को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था, और इस रोक से अभिनेता से नेता बने विजय की फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया है। फिल्म राजनीतिक मसलों पर बनी है और इसी वजह से यह चर्चा में है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक पोस्ट में कहा, "सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'जना नायकन' को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है।" उन्होंने यह भी कहा, "पीएम मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज को दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे।"

एक्टर विजय की यह आखिरी फिल्म

KVN प्रोडक्शंस LLP ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसने बोर्ड को फिल्म का सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगा दी थी। विजय कुछ समय पहले अभिनय की दुनिया छोड़कर राजनीति की दुनिया में आए। इसके लिए हाल ही में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) लॉन्च की है। फिल्म 'जना नायकन' को विजय की राजनीति में एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर बड़े स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है।

मां और बीवी को मारा..फिर दोनों की खोपड़ी से खाया मांस, छत से फेंके टुकड़े, सिकंदर की दरिंदगी देख कांपे लोग

आर्यावर्त संवाददाता

कुशीनगर। कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना इलाके के परसा गांव के रहने वाले 30 साल के सिकंदर की हैवानियत को जिसने भी देखा और उसके बारे में सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब आठ बजे घर की छत पर अलाव के पास बैठी मां रूना देवी और पत्नी प्रियंका की बेरहमी से हत्या के बाद सिकंदर उनकी खोपड़ी का मांस नोचकर खा रहा था।

बीच-बीच में वह मांस के कुछ टुकड़े नीचे फेंक रहा था। यह देख ग्रामीणों को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हत्या का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस मांस खाने की बात से इन्कार कर रही है।

पड़ोसियों को नहीं लगी हत्या की भनक

रोज की तरह सोमवार की सुबह भी पत्नी और मां छत पर अलाव के पास बैठी थीं। वहीं नशे की हालत में सिकंदर पहुंचा। शराब पीने का पत्नी ने विरोध किया तो दोनों में कहासुनी हो गई। इसी गुस्से में सिकंदर ने छत पर रखे पत्थर के टुकड़े को उठाकर प्रियंका के सिर पर पीछे से वार कर दिया। मां बीच बचाव करने गई तो उनके सिर पर भी उसी पत्थर से हमला कर दिया। दोनों के अचेत होने के बाद सिर को कूंच दिया। करीब डेढ़ घंटे तक वह छत पर तांडव मचाता रहा और इसकी भनक तक पड़ोसियों को नहीं लगी।

दो घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया

दिन में करीब 9.30 बजे छत से मांस का टुकड़ा घर के पास सड़क पर फेंकने लगा। उधर से गुजर रहे लोग मांस का टुकड़ा देख रुक गए और रूना, सिकंदर को आवाज देने लगे। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर कुछ युवकों ने छत पर चढ़ने का प्रयास किया तो सिकंदर उन पर से ईंट चलाने लगा।

'मांस का टुकड़ा खा रहा था सिकंदर'

लोगों ने बताया कि छत पर बैठकर सिकंदर मांस का टुकड़ा खा रहा था और इधर-उधर फेंक रहा था। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से उसे दबोच लिया। उसके दोनों हाथ खून से सने थे।

सिकंदर का चेहरा भावशून्य था, जैसे उसे अपनी करतूत पर कोई पछतावा ही नहीं था। पुलिस जब उसे थाने ले जाने लगी तो वह पुलिस वालों पर बार-बार थूक रहा था लेकिन दरवाजे पर मौजूद लोगों से आंख नहीं मिला रहा था। जिस पत्थर के टुकड़े से उसने हत्या की, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है।

नशे की लत, बच्चे न होने से परिवार में था मनमुटाव

परसा गांव के कुछ लोगों ने बताया कि सिकंदर की शादी के चार साल बाद भी कोई औलाद नहीं थी। इसको लेकर परिवार में तनाव था। नशे की लत भी परिवार में कलह का कारण बनी। मां भी सिकंदर की आदतों से परेशान थी। बहू की गोद सूनी थी इसके लिए गांव के आस-पास झाड़-फूंक और मंदिरों तक दौड़ लगाती थी। सिकंदर के पास न तो कोई ठोस रोजगार था और न ही परिवार का ख्याल रखता था। इससे घरवाले भी आहत थे।

सनकी ने पत्थर से सिर कूंचकर मां और पत्नी को मार डाला

कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना इलाके के परसा गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पारिवारिक विवाद में 30 वर्षीय एक युवक ने पत्थर से सिर कूंचकर पत्नी और मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह पत्नी और मां की लाश से मांस नोचकर खा रहा था। हालांकि पुलिस इस बात से इन्कार कर रही है।

चार वर्ष पहले हुई थी सिकंदर की शादी

मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने युवक की बहन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, परसा गांव निवासी सिकंदर (30) पुत्र स्व. बनवारी की शादी चार वर्ष पूर्व देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सवना लक्ष्मण गांव निवासी राजेंद्र गुप्ता की बेटी प्रियंका (28) से हुई थी। शादी के चार साल बाद भी सिकंदर और प्रियंका के कोई संतान नहीं थी।

पत्थर के टुकड़े से किया हमला

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे सिकंदर की पत्नी प्रियंका और मां रूना देवी (60) घर की छत पर अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान सिकंदर नशे की हालत में पहुंचा। वहां किसी बात पर उसकी पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में उसने छत पर रखे पत्थर के टुकड़े से उसके सिर पर हमला कर दिया।

लाशें देख खड़े हो गए लोगों के रोंगटे

रूना ने बहू को बचाने की कोशिश की तो सिकंदर ने उनके सिर पर भी उसी पत्थर से वार कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। छत पर मां-पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या की गई लाश देख कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मालूम हो कि सिकंदर की शादी के एक साल बाद ही पिता की भी एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से परिवार की जिम्मेदारी सिकंदर के ही कंधे पर ही थी। पत्नी और मां की हत्या करने के मामले में आरोपी की बहन की प्राथमिकी पर केस दर्ज कर सिकंदर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

- केशव कुमार, एसपी कुशीनगर

चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1.9 किलो अवैध गांजा बरामद

सुल्तानपुर। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बन्धुआकलां थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को 1 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में की गई।मंगलवार को बन्धुआकलां थाना क्षेत्र में संदिग्धों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ।थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान साकिब उर्फ छोटू पुत्र मुशीर अहमद निवासी ग्राम सिसियाना,थाना जगदीशपुर,जिला अमेठी के रूप में हुई है।पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जनपद में अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम और चिकित्सालय एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। चांदा कोतवाली क्षेत्र स्थित पीपी कमैचा में एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। यहां 14 दिनों के भीतर जुड़वा दो नवजात बच्चों की मौत हो गई, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार, सराय कल्याण निवासी संदीप वैश्य की पत्नी किरण ने 26 दिसंबर को लंभुआ के एक निजी अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। बच्चों की हालत नाजुक होने पर उन्हें पीपी कमैचा स्थित सहारा बाल चिकित्सालय में डॉ. आकाश मिश्रा के यहां भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 27 दिसंबर को एक नवजात की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि दूसरे बच्चे को डॉक्टर ने स्वस्थ बताकर घर भेज दिया, लेकिन हालत ठीक न होने पर वे रोजाना उसे अस्पताल लेकर आते रहे। मंगलवार को इलाज के दौरान दूसरे नवजात ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पिछले दरवाजे से फरार हो गए। मृतक बच्चों के चाचा संदीप उमर वैश्य ने आरोप लगाया कि इलाज पर करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च हो चुके थे। परिजनों ने उच्च अधिकारियों के मौके पर आने तक शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस जांच में जुट गई है। परिजनों ने सीएमओ और चांदा कोतवाली में शिकायत पत्र देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

दो बच्चों के पिता ने करवाया जेंडर चेंज, पत्नी को दो साल तक नहीं लगी भनक, राज खुला तो बोली- अपने दोस्तों से मुझे...

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बच्चों के एक पिता ने गुपचुप तरीके से अपना लिंग परिवर्तन करा लिया और महिला बन गया। विवाह के सात साल बाद जब पत्नी को इस बात की भनक लगी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आव देखा ना ताव, सीधे न्याय मांगने कोर्ट पहुंच गई। पत्नी ने इसे अपने साथ धोखा बताया है। पति से हर्जाने और न्याय की गुहार लगाई है।

मामला बांसगांव क्षेत्र का है। पीड़ित पत्नी के अनुसार, उसकी शादी को सात साल हो चुके हैं और उनकी दो बेटियां भी हैं। पत्नी का आरोप है कि उसका पति दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है, करीब दो साल पहले उसने दिल्ली जाकर अपना लिंग परिवर्तन करा लिया था, लेकिन इस बड़े फैसले की जानकारी परिवार को नहीं दी। हाल ही में जब पत्नी के हाथ

मेडिकल दस्तावेज लगे, तब जाकर इस सनसनीखेज सच्चाई का खुलासा हुआ। न्यायालय में दाखिल अपनी अर्जी में पत्नी ने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि शादी के बाद से ही पति का व्यवहार असामान्य था। वह अक्सर मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। आरोप है कि पति खुद तो अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाता था। साथ पत्नी को भी इसके लिए मजबूर करता था। पीड़ित पत्नी का दावा है कि पिछले वर्ष पति ने उसे बेरहमी से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद से वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर दर-दर भटक रही है।

भरण-पोषण और हर्जाने की मांग

सच्चाई सामने आने के बाद पत्नी ने कोर्ट में भरण-पोषण और हर्जाने की मांग की है। वहीं, दूसरी ओर से पति ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। पति के पक्ष से भी न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई है। फिलहाल, कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

पत्नी को सताई भविष्य की चिंता

पीड़िता का कहना है कि पति के इस कदम ने न केवल उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद कर दिया है, बल्कि उसकी दोनों मासूम बेटियों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। वह अब कानूनी लड़ाई के जरिए अपने और अपने बच्चों के लिए हक की मांग कर रही है।

संभल में गरजा बुलडोजर : तीन मकान तोड़े..दुकान की ध्वस्त, नोटिस के बाद पहुंचे अफसर, इस वजह से हुई कार्रवाई

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। संभल प्रशासन ने सिरसी में ग्राम समाज और खाद के गड्ढों की भूमि पर बने तीन मकानों के अगले हिस्से और दुकान पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हुई। सोमवार को हुई कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ लगी रही।

हालांकि, बुलडोजर के डर से रविवार को ज्यादातर लोगों ने खुद ही निर्माण को तोड़ लिया था। नायब तहसीलदार का कहना है कि पांच लोगों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की गई है। नायब तहसीलदार बबलू कुमार, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल के साथ सिरसी के मोहल्ला शर्की में कर्बला रोड पर पहुंचे।

इसके बाद नगर पंचायत कार्यालय से बुलडोजर मंगवाया गया। दोपहर 12.15 बजे बुलडोजर ने मकानों पर कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर ने एक के बाद एक तीन मकानों के अगले हिस्से को तोड़ा। जिसके बाद एक दुकान को भी ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान लोग भी जुटे रहे।

बुलडोजर की कार्रवाई करीब एक घंटे तक चली। नायब तहसीलदार ने बताया कि सिरसी में गाटा संख्या 1608 ग्राम समाज और खाद्य के गड्ढे का है जो सरकारी भूमि थी। इस पर पूर्व में तहसीलदार न्यायालय के यहां धारा 67 की कार्रवाई चल रही थी। जिसमें न्यायालय के द्वारा बेदखल आदेश हुआ।

इसके बाद अवैध निर्माण करने वाले लोग जिलाधिकारी के यहां अपील में गए। अपील खारिज होने के बाद सोमवार को बेदखली की कार्रवाई कराई है। इसमें पांच लोगों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई हुई है। तीन का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हालांकि लोगों ने रविवार को भी स्वयं निर्माण हटा लिया था।

मलबा गिरने से गेट के शीशे टूटे

मोहल्ला शर्की में बुलडोजर ने जिस दुकान को ध्वस्त किया उसके पीछे इरफान अहमद का मकान है। बुलडोजर के द्वारा निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान मलबा पीछे इरफान अहमद के मकान के गेट पर गिर गया। जिससे गेट के शीशे टूट गए। इस लापरवाही को लेकर उन्होंने आपत्ति की।

सरकार को गरीबों की चिंता नहीं : कांग्रेस

जौनपुर। गरीबी की जगह गरीबों को ही खत्म कर अपनी निरंकुशता और तानाशाही नीतियों को लागू कर संविधान को समाप्त करने का काम कर रही है मोदी सरकार। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रयाग जोन के प्रभारी पूर्व मंत्री राजेश तिवारी ने मुंगराबादशाहपुर के गरियाव बाजार में पार्टी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम सभा कै संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा। कहा कि सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है उन्हें अपने पूजीपती मित्रों को लाभ पहुंचाने का ही काम हो रहा है, उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, मजदूरों और महिलाओं को गारंटी के तहत गांवों में ही रोजगार देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था किंतु भाजपा सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर मनरेगा कानून खत्म करके गरीब मजदूरों का शोषण करना चाहती है। जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों की स्वतंत्रता और गरीबों का अधिकार छीनकर गांवों में ठीकेदारी प्रथा को लागू कर कानूनी रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने वीबी जीरामजी के नाम से नया कानून लायी है।

यूपी में एसआईआर : तिवारी के घर के पते पर फैज मोहम्मद...एक ही घर में 49 लोगों के नाम, किसने भरा मृतकों का फार्म?

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर देहात। अनंतिम विधानसभा मतदाता सूची में छह जनवरी को जारी की गई है। सूची में हैरान करने वाली खामियां सामने आ रही हैं। कहीं तिवारी जी के मकान में मोहम्मद साहब दर्ज हैं तो कहीं शर्मा जी के घर में त्रिपाठी जी रहते दिखाए गए हैं। एक घर में कहीं 18 तो कहीं 49 या इससे अधिक लोग रहते दिखाए गए हैं। वहीं एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर दर्ज हैं। कई मृतकों के नाम भी शामिल हैं। मृतकों का एसआईआर फार्म किसने भरा। परिजन इससे अनजान हैं। खामियां इतनी ज्यादा है कि बीएलओ बताने से बच रहे हैं।

केस एक : दिनेश तिवारी के घर में फैज मोहम्मद समेत तीन मतदाता

विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर-रनियां के दिनेश तिवारी 52 साल के हैं। उनके परिवार में पांच मतदाता हैं। उनके ही घर के पते पर तीन अन्य

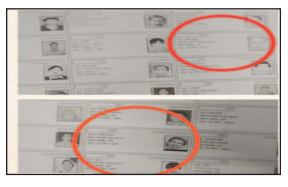

मतदाता दिख रहे हैं। इसमें फैज मोहम्मद का नाम भी है। अन्य तीन मतदाता फैज मोहम्मद के परिवार के ही हैं। चौथा मतदाता किस परिवार का है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब दिनेश घर पर दर्ज खान साहब के नाम को लेकर चिंतित हैं।

केस दो : एक पते पर 48 मतदाता

अकबरपुर-रनियां विधानसभा क्षेत्र के धर्मेंद्र शर्मा 39 साल के हैं। उनके परिवार में पत्नी समेत पांच सदस्य हैं। उनके ही घर के पते पर 48 अन्य मतदाता भी कच्ची मतदाता सूची में दिख रहे हैं। इसमें कोई त्रिपाठी, वर्मा और कुशवाहा भी हैं। अब धर्मेंद्र मतदाता सूची में इस स्थित से चिंतित हैं।

केस तीन : पत्नी का नाम दूसरे के घर के पते पर दर्ज

अकबरपुर-रनियां विधानसभा क्षेत्र की मसौदा सूची में आशीष (51) को उनकी पत्नी अनुराधा से अलग घर में दर्शाया गया है। कारोबारी आशीष के परिवार में सात मतदाता हैं। मां, भाइयों व उनकी पत्नियों समेत छह नाम एक घर के पते पर हैं, जबकि उनकी पत्नी का नाम दूसरे के घर के पते पर है।

साल भर पहले दिवंगत तो किसने भरा एसआईआर फॉर्म

रूरा के शास्त्रीनगर निवासी रजनीकांत का निधन 19 अगस्त 2024 को हो गया चुका है। कच्ची सूची में उनका नाम दर्ज है। बीएलओ ने घर-घर फॉर्म बांटे। भरे फार्म जमा कराए और एप पर डिजिटाइज किए। सवाल यह है कि दिवंगत का एसआईआर फॉर्म किसने भरा।

मतदाता सूची में एक मकान नंबर पर यदि अधिक संख्या में मतदाता हैं तो ऐसे प्रकरणों की जांच कराई जाएगी। गलती से अनंतिम सूची में मृतकों के नाम दर्ज हैं तो फार्म-7 भरकर ये नाम खारिज किए जाएंगे। इस सूची में परिवार के सदस्यों के बिखराव की स्थिति 89 बूथ बढ़ने से हुई है। इसमें सुधार किया जाएगा। -कपिल सिंह, डीएम /जिला निर्वाचन अधिकारी

एसआईआर से पहले दिवंगत फिर भी कच्ची सूची में नाम दर्ज

अकबरपुर-रनियां विधानसभा की कच्ची मतदाता सूची में रूरा के गणेशगंज निवासी सूर्यमुखी का नाम दर्ज है। बीमारी के चलते सूर्यमुखी का निधन 27 नवंबर 2025 को हो चुका है। बीते साल चार दिसंबर 2025 को एसआईआर शुरू हुआ। इसके बाद भी कच्ची सूची में मृतक का नाम दर्ज है।

लोकतांत्रिक आवाजों का दमन चिंताजनक

जौनपुर। देश और प्रदेश में मौजूदा सरकार द्वारा अपनाई जा रही दमनकारी नीतियाँ यह साबित कर रही हैं कि भारत आज एक अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र में विरोध, असहमति और सवाल पूछना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आज उसी अधिकार को कुचलने का काम किया जा रहा है। एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष अमन सिन्हा ने कहा कि प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यह कार्रवाई न सिर्फ अलोकतांत्रिक है, बल्कि यह सरकार की डर और असहिष्णुता की मानसिकता को भी उजागर करती है। एनएसयूआई यह स्पष्ट करना चाहती है कि सरकार छात्रों, युवाओं और विपक्ष की आवाज से भयभीत है। सवालों से भागने के लिए पुलिस-प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह रवैया लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और संविधान पर सीधा हमला है। एनएसयूआई इस अघोषित आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा करती है।

पारूल विश्वविद्यालय में चिकित्सक को मिला क्षारसूत्र अवार्ड, जनपद में हर्ष

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। बड़ोदरा (गुजरात) स्थित प्रतिष्ठित पारूल विश्वविद्यालय में आयोजित क्षारसूत्र परीक्षा में सुलतानपुर जनपद के सुमन हॉस्पिटल, सुलतानपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. डी.के. गुप्ता को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्वविद्यालय के डीन/कुलपति ओ.पी. द्ववे द्वारा प्रदान किया गया।

क्षारसूत्र परीक्षा में देशभर से कुल 60 चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से उत्तर प्रदेश के मात्र चार चिकित्सक ही सफल हो सके। इस कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर डॉ. डी.के. गुप्ता ने न केवल सुलतानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। सफल चिकित्सकों को कुलपति द्वारा अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉ. डी.के. गुप्ता की इस उपलब्धि पर चिकित्सा जगत में हर्ष की लहर है। इस क्रम में डॉ. ए.के. सिंह, डॉ. संजय, डॉ. अमर, डॉ. दीप, डॉ. डी.पी. सिंह एवं डॉ. अमन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं रामबरन पीजी कॉलेज, जयसिंहपुर, सुलतानपुर के प्रशासक संजय सिंह ने भी इस उपलब्धि को जनपद के लिए गर्व का विषय बताया और खुशी जाहिर की। इसके अतिरिक्त जिले के पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने भी डॉ. गुप्ता को शुभकामनाएं दीं। बधाई देने वालों में पत्रकार संजय सिंह, पंकज पाण्डेय, मनोज मिश्र, घनश्याम वर्मा, अनिल सिंह, सलमान, राहुल सहित अन्य लोग शामिल रहे। डॉ. डी.के. गुप्ता की यह सफलता युवाओं और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है, जिससे सुलतानपुर जनपद की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त हुई है।

घर सुल्तानपुर फाउंडेशन की मुहिम

सुल्तानपुर। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर नदियों में स्नान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। नदी स्नान को शारीरिक शुद्धि के साथ-साथ मानसिक और आध्यात्मिक शांति का माध्यम माना गया है। आज के समय में नदियाँ प्रदूषण की मार झेल रही हैं और समाज, विशेषकर युवाओं का जुड़ाव नदियों व प्रकृति से धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसी चिंता और जिम्मेदारी के भाव से घर सुल्तानपुर फाउंडेशन ने एक जागरूकता अभियान का आह्वान किया है। फाउंडेशन की ओर से अपील की जाती है कि 15 जनवरी, मकर संक्रांति के दिन देश-प्रदेश में जहां भी लोग हों, वहां की नदी में स्नान करें। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि नदियों के महत्व को समझने, उनके संरक्षण के प्रति संवेदनशील होने और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने का प्रयास है।

25 वें स्थापना दिवस पर समाजसेवियों को किया सम्मानित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। राजकीय जूनियर हाई स्कूल सलाहपुर, भदैया सुल्तानपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्व विश्वास संस्थान द्वारा 25वाँ स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में स्वयंसेवी जगत के पुरोधा स्वविश्वास संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष पानी संस्थान अयोध्या के मुख्य कार्यकारी भारत भूषण सिंह, संस्थापक सदस्य पूर्व महाप्रबंधक भूमि विकास प्राधिकरण(रेलवे) पूर्व विधायक लंभुआ देवमणि द्विवेदी, डाक्टर सीताशरण त्रिपाठी (स्वतंत्र निदेशक कोल खनिज विभाग) ने स्वामी विवेकानंद के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उक्त अवसर पर स्वविश्वास संस्थान के सचिव राकेश द्विवेदी ने सभी का सम्मान किया एवं स्वविश्वास संस्थान के 25 वर्षों के सफर को विस्तार से

बताया। इस अवसर पर संस्थान ने कुछ समाजसेवियों को सम्मानित किया गया जिसमें 32 वर्ष की कम आयु में ही 42 बार रक्तदान करने वाले रक्त वीर अखिलेश सिंह पर्वत को भारत भूषण ने प्रशस्तपत पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया, इसी समय पत्रकारिता के क्षेत्र में निर्भीक पत्रकारिता करने का काम करने वाले नौजवान आलोक द्विवेदी को देवमणि द्विवेदी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर कोषाध्यक्ष देशार्थ ने जगदीशपुर के आशिक अली को कृषि के क्षेत्र में जलवायु आधारित खेती करने के लिए प्रशसति पत्र देकर सम्मानित किया उक्त अवसर पर संस्थान द्वारा क्षेत्र की किशोरियों को भी सम्मानित किया ग्राम प्रधान सलाहपुर सरोजा देवी, जगदीशपुर के प्रधान जय प्रकाश यादव, बदरुद्दीनपुर के प्रधान केदारनाथ यादव को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। भदैयाँ सामुदायिक स्वास्थकेन्द्र के अधिक्षक डाक्टर आर पी सिंह, आशा, ऐनम, सी एच वो को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी रामसहाय शर्मा ने किया एंव संचालन सुरेश तिवारी ने किया। इस अवसर पर लम्भुआ निवासी व्यापारी नेता जयशंकर तिवारी, अनुपम पाठक, राजेश चतर्वेदी, दुर्गेश मिश्रा, विपिन तिवारी, सुनीता यादव, संजूयादव, वन्दना दुबे उपस्थित थे। धन्यवाद और आभार भाषण श्रीमती गरिमा सिंह ने दिया।

प्रगति' नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त प्रतीक, उत्तर प्रदेश बना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन: मुख्यमंत्री योगी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी 'प्रगति' केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं है, बल्कि यह नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त उदाहरण है। मंगलवार को आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रगति' उस प्रशासनिक मॉडल को दर्शाता है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी थी और वर्ष 2014 के बाद जिसे राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सुदृढ़ किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति ने यह प्रमाणित किया है कि जब इरादा, तकनीक और जवाबदेही एक साथ आती हैं, तो परिणाम स्वतः सुनिश्चित हो जाते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूती देते हुए प्रगति एक ऐसा प्रभावी मंच बनकर उभरा है, जहां अंतर-मंत्रालयीय और अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से जटिल से जटिल समस्याओं का भी समयबद्ध समाधान संभव हुआ है।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति मॉडल की अवधारणा वर्ष 2003 में गुजरात में 'स्वागत' के रूप में प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। यही मॉडल आगे चलकर 'प्रगति' के राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में विकसित हुआ, जिसने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और सिस्टम रिफॉर्म के क्षेत्र में टीम इंडिया अप्रोच को मजबूती प्रदान की।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति केवल एक रिव्यू मैकेनिज्म नहीं, बल्कि एक व्यापक गवर्नेंस रिफॉर्म है। इसने शासन को फाइल-केंद्रित संस्कृति से निकालकर फील्ड आधारित और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली की ओर अग्रसर किया है। इसके माध्यम से निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत की बर्बादी पर रोक लगी है और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति के प्रभाव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके माध्यम से 86 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है। इनमें से 377 प्रमुख परियोजनाओं की प्रत्यक्ष समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि कुल 3162 मुद्दों में से 2958 का समाधान हो चुका है, जो शासन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति मॉडल राज्य के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सर्वाधिक शहरों में मेट्रो सेवाएं, बेहतर एयर कनेक्टिविटी, देश की पहली रैपिड रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और रोपवे जैसी परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ी हैं, जिनके पीछे निरंतर समीक्षा और समस्या समाधान का प्रभावी मंच प्रगति रहा है।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास 10.48 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 330 परियोजनाओं के साथ देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। इनमें परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से 2.37 लाख करोड़ रुपये की लागत की 128 परियोजनाएं पूर्ण होकर कमीशन हो चुकी हैं, जबकि 8.11 लाख करोड़ रुपये की 202 परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रगति पर हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए सभी अड़चनों का समाधान कर परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में प्रगति एक मजबूत आधार बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रगति मॉडल ने उत्तर प्रदेश को रेलवे, हाईवे और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में यदि परियोजनाओं, एमओयू और अनुमतियों में देरी होती है तो निवेशक दूसरे राज्यों की ओर रुख करता है। प्रगति ने वर्षों में पूरी होने वाली प्रक्रियाओं को महीनों में और महीनों की प्रक्रियाओं को दिनों में समेटते हुए परियोजनाओं को तय समय-सीमा में धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम प्रदान किया है।मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 4.19 लाख करोड़ रुपये की लागत के 65 बड़े प्रोजेक्ट प्रगति के अंतर्गत शामिल हैं।

मकर संक्रांति पर संगम तट बना आस्था और आधुनिकता का संगम, यूपीएसटीडीसी की टेंट सिटी श्रद्धालुओं के लिए नया आकर्षण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मकर संक्रांति सहित अन्य प्रमुख स्नान पर्वों पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए संगम तट पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य टेंट सिटी विकसित की गई है। देश-दुनिया से श्रद्धालुओं का संगम की पुण्य धारा में स्नान के लिए निरंतर आगमन हो रहा है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संगम तट की रेत पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टेंट कॉलोनी बसाई गई है, जो कल्पवासियों और पर्यटकों के लिए आस्था के साथ-साथ आकर्षण का नया केंद्र बनकर उभरी है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रयागराज के अरैल सेक्टर-7 में त्रिवेणी पुष्प से पहले विकसित इस टेंट कॉलोनी में कुल 50 आधुनिक कॉटेज तैयार किए गए हैं। इन कॉटेज की ऑनलाइन बुकिंग यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट के माध्यम से की जा रही है। टेंट कॉलोनी को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें 15 हजार रुपये किराए वाला प्रीमियम, 11 हजार 500 रुपये का लग्जरी और 7 हजार 500 रुपये का डीलक्स कॉटेज शामिल है। इनमें 12 प्रीमियम, 8 लग्जरी और 30 डीलक्स टेंट बनाए गए हैं। इन सभी में ठहरने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित शुल्क में सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है।उन्होंने बताया कि टेंट कॉलोनी परिसर में यज्ञशालाओं का निर्माण किया गया है, जहां लगातार भजन-कीर्तन हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव मिल रहा है। संगम तट को सांस्कृतिक रंग देने के उद्देश्य से कलाग्राम भी विकसित किया गया है, जहां स्थानीय शिल्प और लोककला को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और आगंतुकों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया जा रहा है।पर्यटन मंत्री ने कहा कि माघ मेला 2026 के दौरान रोजगार और नवाचार को विशेष बढ़ावा मिला है। संगम टेंट कॉलोनी में एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी के माध्यम से प्रयागराज की पारंपरिक मूंज कला के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु मूंज से बनी डलिया, पेन स्टैंड, रोटी रखने के बर्तन, गमले और सजावटी वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं। नैनी क्षेत्र के महेवा इलाके की यह पारंपरिक मूंज कला, जिसे चांद जैसी कारीगर वर्षों से आगे बढ़ा रही हैं, अब आधुनिक स्वरूप में सामने आकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है।जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप माघ मेला अब केवल आस्था का आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि यह पर्यटन, रोजगार और स्थानीय कला को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बन चुका है। यूपीएसटीडीसी द्वारा विकसित संगम टेंट कॉलोनी इसका जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक वातावरण का समग्र अनुभव मिल रहा है।

हुसैनगंज में जानलेवा हमले के चार आरोपी गिरफ्तार, धारदार हथियार से युवक पर किया था हमला

आर्यावर्त संवोददाता

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के मध्य जोन अंतर्गत थाना हुसैनगंज पुलिस ने जान से मारने की नीयत से किए गए हमले के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने यह कार्रवाई थाना हुसैनगंज पर दर्ज मुकदमा संख्या 0002/2026 के तहत की है, जिसमें आरोपियों पर एकराय होकर धारदार हथियार से हमला करने का गंभीर आरोप है।पुलिस के अनुसार यह मुकदमा 12 जनवरी 2026 को पुराना किला क्षेत्र निवासी नान बच्ची द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि नामजद अभियुक्तों ने एकजुट होकर वादिनी के पुत्र पर धारदार हथियार से हमला किया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।13 जनवरी 2026 को थाना हुसैनगंज पुलिस टीम ने अभियोग से संबंधित चारों आरोपियों सुहैल पुत्र रज्जब, समद पुत्र सुलेमान उर्फ पठान, अरमान पुत्र स्वर्गीय कल्लू और कृष्णा पुत्र स्वर्गीय रामदुलारे को एलिवेटेड रोड के किनारे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त पुराना किला और आसपास के क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों और जनपदों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त अरमान का पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ वर्ष 2020 में थाना हुसैनगंज में धारा 188 और 271 के तहत दो मुकदमे दर्ज हैं।

सोनू कश्यप हत्याकांड के विरोध में हजरतगंज में सपा का जोरदार प्रदर्शन

» कार्यकर्ता हिरासत में, इको गार्डन भेजे गए

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मेरठ में सोनू कश्यप की नृशंस हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया और हत्याकांड के दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुके हैं और आमजन, विशेषकर पिछड़े और कमजोर वर्ग, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया। पुलिस कार्रवाई के बावजूद कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ और उन्होंने हिरासत के दौरान भी न्याय की मांग को दोहराया। इको गार्डन पहुंचने पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजपाल कश्यप ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी।हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में प्रमुख रूप से शिवम कश्यप, प्रदेश महासचिव समाजवादी युवजनसभा, एडवोकेट संदीप कश्यप, जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजनसभा सीतापुर, राज साहनी, एडवोकेट जीतू कश्यप, एडवोकेट शिवम कश्यप, नीरज पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, हरनाम यादव हरदोई, अंकित यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में सोनू कश्यप को न्याय दिलाने की मांग की।डॉ. राजपाल कश्यप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सोनू कश्यप को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएगी और प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था के सवाल पर जवाबदेह बनाएगी। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार उन्हें रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

निवेश के नाम पर 1.92 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, फर्जी आधार–पैन से खाते खोलने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। निवेश में अधिक मुनाफे का झांसा देकर करीब दो करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने वाले शातिर अपराधी को साइबर क्राइम पुलिस थाना, कमिश्नरेट लखनऊ की टीम ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी पहचान बनाकर लोगों से संपर्क करता था और निवेश के नाम पर भारी रकम हड़प लेता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कूटरचित आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किए हैं।साइबर क्राइम थाना लखनऊ के अनुसार 2 जून 2025 को पीड़ित शलभ पाण्डेय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल नंबर पर एक महिला ने खुद को "भाविका शेट्टी" बताते हुए व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। बातचीत और कॉल के माध्यम से मित्रता स्थापित करने के बाद आरोपी गिरोह ने निवेश कर अधिक लाभ

कमाने का झांसा दिया और अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 92 लाख 92 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। बाद में यह पूरा मामला साइबर धोखाधड़ी का निकला। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम लखनऊ में अपराध संख्या 87/2025 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(डी) में मुकदमा दर्ज किया गया।मामले के अनावरण के लिए पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर साइबर क्राइम थाना लखनऊ में विशेष टीम का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक लेन-देन के विश्लेषण के आधार पर मुख्य अभियुक्त इमरान गाजी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका एक्सिस बैंक खाता फ्रीज होने के बाद उसने फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाए और शहजाद नामक व्यक्ति के संपर्क में आकर विभिन्न बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए खाते खुलवाए। इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित से ठगे गए पैसों में से 54 लाख रुपये सीधे आरोपी के खाते में ट्रांसफर हुए थे। बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण में यह भी खुलासा हुआ कि महज एक महीने के भीतर आरोपी के खातों में करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ है। आरोपी द्वारा अपनाए गए तरीके में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी पहचान बनाकर संपर्क करना, निवेश में मोटे मुनाफे का लालच देना, फर्जी दस्तावेजों से खोले गए बैंक खातों का उपयोग करना और कमीशन पर रकम की निकासी कराना शामिल है।गिरफ्तार अभियुक्त इमरान गाजी निवासी मिश्रपुर डिपो, थाना गुड़म्बा, लखनऊ का रहने वाला है और उसकी उम्र 34 वर्ष बताई गई है। उसके खिलाफ इसी मामले में साइबर क्राइम थाना लखनऊ में आपराधिक इतिहास दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

अल्टीमेटम बेअसर, न हुई एफआईआर ना होगी हड़ताल, प्रशासन ने मांगे घटना के सबूत

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल नहीं होगी। शासन ने केजीएमयू प्रशासन से नौ जनवरी को हुई घटना के और सबूत मांगे हैं। नौ जनवरी को कुलपति कार्यालय पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद केजीएमयू के पांचों संगठन ने एफआईआर न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी। शासन और केजीएमयू प्रशासन से हुई वार्ता के बाद फिलहाल सभी कार्य बहिष्कार न करने के लिए तैयार हो गए हैं।

केजीएमयू में धर्मांतरण के प्रयास का मुद्दा फिलहाल गर्माया हुआ है। इसी मामले में नौ जनवरी को राज्य महिला आयोग की आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के केजीएमयू पहुंचने के बाद जमकर हंगामा हुआ था। अपर्णा यादव के समर्थकों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय पर हंगामा किया था। इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई थी।

लखनऊ में स्मैकियों ने जमकर किया हंगामा...कई लोगों को पीटा, एक शख्स को मारा चाकू

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। निशातगंज की गलियां नशेड़ियों का अड्डा बन गई हैं। आए दिन चोरी और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। एक गैंग यहां पर रेलवे लाइन के किनारे स्मैक का धंधा कर रहा है। यही लोग विरोध करने वालों से मारपीट करते हैं।

सोमवार सुबह पार्क में स्मैक पीने से मना करने पर स्मैकियों ने मारपीट की। आठवीं गली निवासी मो. आरिफ ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसने गली में स्मैक बेचने से मना किया तो जरीना, नूरी, शाहीन, कोमल ने मारपीट की। ईंट-पत्थर से मारा, जिसमें शबाना, अरशी को चोट आई है। एक किन्नर के संरक्षण में चल रहे स्मैक का धंधा करने वालों ने माली के साथ भी मारपीट की।

सातवीं गली स्थित मेवा नर्सरी कॉलोनी निवासी शिवम ने महानगर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह नगर निगम में अस्थायी माली हैं।

सोमवार की सुबह 7:30 बजे पार्क का ट्यूबवेल चलाने पहुंचे तो वहां पर चार लोग बैठकर स्मैक पी रहे थे। उन्होंने पार्क में बैठकर नशा करने से मना किया तो चारों उग्र हो गए।

चारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना किया तो पास में रहने वाले ईदू, अनुराग, गोलू और अमन सोनकर हाथ में धारदार हथियार लेकर मारने दौड़े। जान बचाने के लिए उन्होंने पार्क में घुसकर गेट बंद किया तो चारों गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस आए और लाठी-डंडों से पीटने लगे। शोर-गुल सुनकर उनके ताऊ राजेश बचाने पहुंचे तो आरोपितों ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। आरोप है कि इंदू ने चाकू से उनके सीने पर वार करने का प्रयास किया जो उनके पेट में लगा। घटना में राजेश और शिवम को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस ने छह घंटे बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया और कार्रवाई में सुस्ती दिखाई। महानगर के सहायक पुलिस आयुक्त अंकित कुमार ने बताया कि शिकायत पर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

रात तक करते रहे हंगामा

स्मैकियों ने कई चरणों में मारपीट की और धमकाया। असुरक्षित लोगों ने कई बार पुलिस को फोन कर बुलाया, लेकिन पुलिस के जाते ही फिर से हंगामा करने लगते।

सुशांत गोल्फ सिटी में युवक की गला रेतकर हत्या, पहचान न हो इसलिए शव जलाने की कोशिश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव भागीरथी एनक्लेव की बाउंड्री के पास लाकर फेंक दिया गया। पहचान न हो सके, इसके लिए शव जलाने की भी कोशिश की गई। शुक्रवार सुबह युवक का 50 प्रतिशत जला शव झाड़ियों में मिला। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार सुबह एक महिला ने झाड़ियों में युवक का अधजला शव पड़ा देखा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस को छानबीन में युवक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले। शव प्लास्टिक की पन्नी व चादर से लपेटा गया था। पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाकर शव की पहचान की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कुछ नमूने लिए हैं। इसके बाद शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। इंस्पेक्टर का कहना है कि पहचान के लिए शव को 72 घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस पर रखा जाएगा। इसके बाद भी शिनाख्त नहीं होती है तो पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि युवक की उम्र 25 वर्ष के आसपास है। छानबीन में पता चला है कि हत्या कहीं और करने के बाद शव भागीरथी एनक्लेव अपार्टमेंट के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया।

हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के किसी भी तरह के समायोजन पर लगाई रोक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन -3 मामले में आगे किसी कार्यवाही पर 19 जनवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को नियत करके अंतरिम आदेश दिया कि मामले की इस अगली सुनवाई की तिथि तक बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर, समायोजन -3 मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि इस अंतरिम आदेश की राहत, इस याचिका के साथ संबद्ध 11 अन्य याचिकाओं के याची शिक्षकों को भी उपलब्ध होगी। कोर्ट ने यह आदेश प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन/ स्थानांतरण - 3 के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया। न्यायमूर्ति

श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश बाराबंकी की संगीता पाल समेत 29 प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर दिया। याचिकाओं में 14 नवंबर 2025 के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षकों के समायोजन/ स्थानांतरण के शासनादेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है।

याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच जी एस परिहार का कहना था कि यह शासनादेश आर टी ई अधिनियम समेत बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1981 के नियमों का उल्लंघन करने वाला है। इसके नियम 21 के तहत शिक्षक की सहमति के बाहर समायोजित न किए जाने की दलील दी। कहा इस समायोजन से जहां शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर पड़ रहा है, वहीं अन्य विसंगतियां भी पैदा हो रही हैं।

उधर, मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने मामले को 19 जनवरी को फाइनल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बीच याचियों को मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। साथ ही राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने का समय दिया है।

सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर नगर निगम का बड़ा कदम, वार्षिक मेडिकल जांच और कैंसर स्क्रीनिंग अनिवार्य

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत, सुरक्षित और मानवीय बनाने की दिशा में नगर निगम लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत सभी सफाई श्रमिकों के लिए अब वार्षिक चिकित्सा परीक्षण और कैंसर स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समस्त जोनल सेनेटरी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।निर्देशों के अनुसार नगर निगम के अधीन कार्यरत सभी नियमित, संविदा तथा कार्यदायी संस्थाओं के सफाई कर्मियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण और कैंसर स्क्रीनिंग एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। यह जांच निकटतम राजकीय चिकित्सालय में कराना सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम का मानना है कि सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी से न केवल उनके जीवन की सुरक्षा होगी, बल्कि नगर की स्वच्छता व्यवस्था भी अधिक प्रभावी और सुदृढ़ हो सकेगी।नगर स्वास्थ्य अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने बताया कि सफाई कर्मियों की यह चिकित्सा जांच निकटतम राजकीय चिकित्सालय, 108 अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा शहर के 8 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से किसी एक में कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य होगा और एक सप्ताह के भीतर इसकी सूचना संबंधित स्तर पर उपलब्ध करानी होगी। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत सभी कर्मियों की ओपीडी पर्ची, जांच रिपोर्ट, चिकित्सकीय परामर्श पत्र तथा अन्य संबंधित अभिलेख विधिवत संकलित किए जाएं और सुरक्षित रूप से रखे जाएं।

NCP की दरार खत्म ! पवार परिवार की चाल से महाराष्ट्र की राजनीति में आया नया मोड़

महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से चली आ रही राकांपा की पारिवारिक और राजनीतिक फूट पर फिलहाल विराम के संकेत मिलते दिख रहे हैं। दरअसल, पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए राकांपा के दोनों गुटों ने संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है। यह वही राकांपा है जो बीते डेढ़ वर्ष से दो हिस्सों में बंटी हुई थी और एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक राजनीति कर रही थी। संयुक्त घोषणापत्र में गड्ढा मुक्त सड़कें, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। यह घोषणापत्र स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है लेकिन इसका राजनीतिक संदेश दूर तक जाता है।

घोषणापत्र जारी करने के मौके पर दोनों गुटों के नेताओं का एक साथ मंच साझा करना अपने आप में असाधारण दृश्य रहा। अजित पवार ने इस दौरान कहा कि परिवारिक तनाव समाप्त हो चुके हैं और दोनों पक्षों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी फिर से एकजुट हो। उन्होंने संकेत दिया कि फिलहाल नगर निगम चुनावों में साथ आने का निर्णय लिया गया है लेकिन भविष्य में राजनीतिक एकता की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। शरद पवार गुट की ओर से भी बयानबाजी का स्वर बदला हुआ नजर आया। तल्खी की जगह संयम और आक्रामकता की जगह राजनीतिक परिपक्वता दिखाई दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल स्थानीय तालमेल नहीं बल्कि सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इस घटनाक्रम ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। क्योंकि राकांपा का एक गुट सत्तारुढ़ गठबंधन एनडीए में है जबकि दूसरा गुट विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में दोनों का साथ आना राजनीतिक समीकरणों को हिलाने वाला कदम है।

देखा जाये तो महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर यह साबित कर रही है कि यहां विचारधारा नहीं बल्कि सत्ता ही अंतिम सत्य है। राकांपा का विभाजन किसी वैचारिक मतभेद का परिणाम नहीं था बल्कि सत्ता के समीकरणों की उपज था। अब दोनों गुटों का एक मंच पर आना भी किसी आत्ममंथन का नहीं बल्कि सत्ता की मजबूरी का नतीजा है। संयुक्त घोषणापत्र स्थानीय विकास के नाम पर जारी किया गया है लेकिन इसका असली मकसद कार्यकर्ताओं को यह संकेत देना है कि पवार परिवार की सियासी दरार भर रही है। यह संदेश जितना नीचे तक जाएगा, उतना ही तेजी से राजनीतिक गणित बदलेगा। यदि राकांपा के दोनों गुट पूरी तरह से एक हो जाते हैं तो इसका पहला और सीधा असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा। अजित पवार का एनडीए के साथ रहना तब अर्थहीन हो जाएगा जब पार्टी की कमान फिर से एकजुट होकर शरद पवार के प्रभाव क्षेत्र में लौटेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए यह घटनाक्रम जीवनदान जैसा हो सकता है। महाराष्ट्र जैसे निर्णायक राज्य में यदि राकांपा एकजुट होकर विपक्षी खेमे में मजबूती से खड़ी होती है तो यह न केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा स्तर पर भी भाजपा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बिखराव रही है और पवारों का साथ आना इस कमजोरी पर मरहम बन सकता है। हालांकि अजित पवार पार्टी की कमान चाचा शरद पवार को वापस सौंपेंगे इसकी संभावना नगण्य ही है। लेकिन यह तस्वीर का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू उतना ही खतरनाक है। यदि राकांपा की एकता केवल नगर निगम और सीमित राजनीतिक सौदे तक सिमटी रहती है तो इससे विपक्षी गठबंधन इंडिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। जनता पहले ही अवसरवादी राजनीति से त्रस्त है और ऐसे प्रयोग उस अविश्वास को और गहरा करेंगे।

एनडीए के लिए यह स्थिति असहज करने वाली है। जिस अजित पवार को सत्ता संतुलन के लिए साथ लिया गया था वही यदि परिवारिक एकता के नाम पर अलग दिशा में चले जाते हैं तो यह गठबंधन की कमजोरी उजागर करेगा। यह संदेश जाएगा कि सत्ता के लिए बनाए गए गठबंधन टिकाऊ नहीं होते। बहरहाल, राकांपा का यह संयुक्त कदम महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह अध्याय एकता, विश्वास और स्थायित्व की ओर जाएगा या फिर अवसरवाद और अस्थायी समझौतों की कहानी बनेगा, यह आने वाले चुनाव तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि पवार परिवार की हर चाल पूरे राजनीतिक शतरंज को हिला देने की ताकत रखती है।

चीन से क्या हम भाषायी बोध सीख सकते हैं

उमेश चतुर्वेदी

अंग्रेजी का पहला वैश्विक विस्तार ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौर में हुआ और दूसरी बार उसका प्रसार रीगन-थैचर की जोड़ी के आर्थिक उदारीकरण के बढ़ते कदमों के साथ हुआ

हिंदी के संदर्भ में देखें तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच शाब्दिक ही नहीं, भावात्मक फर्क भी है। फिर भी एक बड़ा वर्ग हिंदी को राष्ट्रभाषा भी मानता है। यही वजह है कि हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के नौवें महीने की दस्तक के साथ ही, हर सरकारी दफ्तर राजभाषा पखवाड़े या महीने को लेकर उत्साह से भर उठता है। कुछ ऐसा ही पड़ोसी चीन में भी अब होता नजर आ रहा है। अब वहां सितंबर का तीसरा सप्ताह 'राष्ट्रीय सामान्य भाषा और लिपि' को समर्पित होगा। भारत और चीन के सितंबर महीने के भाषायी उत्साह में एक अंतर रहेगा, राष्ट्रभाषा बनाने की आस में हिंदी के राजभाषा ओहदे को याद किया जाएगा, जबकि चीन अपनी मंदारिन भाषा को बाकायदा राष्ट्रभाषा के तौर पर और आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होगा।

भाषायी चिंतन और व्यवहार को लेकर भारत और चीन को लेकर तकरीबन एक ही सोच है। भारत में एक मानस ऐसा है, जिसे हिंदी की कीमत पर भी पर अंग्रेजी स्वीकार्य है। यह धारा मानती है कि वेगवान आर्थिक विकास की वजह से चीन का भाषायी व्यवहार भी इसी भारतीय मानस की तरह बदल चुका है। बेशक चीन ने अंग्रेजी सीखने-सिखाने की दिशा में भरपूर निवेश किया है। अपनी आर्थिक ताकत के चलते पश्चिम के नामी विश्वविद्यालयों में चीनी सत्ता प्रतिष्ठान अपने लिए अध्ययन पीठ स्थापित कर चुका है। गौर करने की बात है कि उसने यह सब अलग और अतिरिक्त अनुशासन और ज्ञान के साधन के तौर पर किया है, भारत की तरह अपनी भाषा, विशेषकर हिंदी की कीमत पर ऐसा नहीं किया है।

अंग्रेजी का पहला वैश्विक विस्तार ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौर में हुआ और दूसरी बार उसका प्रसार रीगन-थैचर की जोड़ी के आर्थिक उदारीकरण के बढ़ते कदमों के साथ हुआ। इस संदर्भ में चीन और भारत के भाषायी चिंतन और व्यवहार फर्क साफ नजर आता है। पिछली सदी के अस्सी के दशक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख देंग झिआओपिंग ने आर्थिक खुलेपन की नींव रखी। यह 1978 का साल था। इसके ठीक दो साल बाद भारत में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और उन्होंने भी धीरे-धीरे इंस्पेक्टर राज कम करने की शुरूआत की। उनकी उदारीकरण की सोच को राजीव गांधी ने परवान चढ़ाया। 1991 के आम चुनावों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पहली बार समाजवादी आर्थिक नीतियों के बरक्स उदारीकरण का वादा किया। तब से अब तक की दोनों देशों की आर्थिक विकास यात्रा को देखें तो अंतर साफ नजर आता है। चीन आज अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। उसकी तेज आर्थिक यात्रा के समानांतर अंग्रेजी का विस्तार नहीं दिखता। जबकि भारत में इसके ठीक उलट नजारा दिखता है।

उदारीकरण के बरक्स दोनों देशों के भाषायी चिंतन में भी फर्क नजर आता है। यह फर्क ही है कि चीन अब अपनी मंदारिन भाषा और उसकी लिपि को लेकर सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते को समर्पित कर रहा है। चीन की सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था 'राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा' की स्थाई समिति द्वारा बीते 27 दिसंबर को इससे जुड़ा कानून पारित करना इसी सोच का प्रतीक है। इस कानून में हर वर्ष सितंबर के तीसरे सप्ताह को 'राष्ट्रीय सामान्य भाषा और लिपि संवर्धन एवं प्रचार सप्ताह' के रूप में मनाना तय किया गया है। यह कानून पुराने राष्ट्रीय भाषा कानून में संशोधन के बाद आया है। चीन में दो तरह की मंदारिन का प्रयोग होता है, एक लिखित और दूसरी मौखिक। इस कानून में दोनों तरह की भाषाओं का ध्यान रखा गया है। चीन अपनी भाषा और लिपि को अपने राष्ट्र का प्रतीक मानता है। चीन में इन दिनों प्रौद्योगिकी और डिजिटल जगत में लगातार प्रगति हो रही है। यहां ऑडियो-विजुअल प्रोग्रामिंग और गेमिंग भी बढ़ी है। चीन का भाषायी कानून इन सबमें इस्तेमाल होने वाली भाषा के साथ कदमताल करने का प्रयास है। कहा जा सकता है कि चीनी राष्ट्रभाषा और लिपि कानून में यह संशोधन तेजी से विकसित हो रही संचार प्रौद्योगिकियों और ऑनलाइन सामग्री के विस्तार के बीच भाषा के मानकीकरण को मजबूत करने की कोशिश है। इस कानून में साइबरस्पेस प्रशासन को लेकर भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत अब ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वेब सीरीज, ऑनलाइन फिल्मों, ऑनलाइन गेम और अन्य डिजिटल प्रकाशनों में मानक चीनी भाषा यानी मंदारिन और मानकीकृत चीनी अक्षरों को मूल भाषा के रूप में उपयोग करना जरूरी होगा। इसके साथ ही चीन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, कॉन्फ्रेंस, इवेंट्स आदि के साइनबोर्ड, लेबल या प्रमोशनल मैटीरियल में विदेशी भाषाओं के साथ ही मानक चीनी भाषा भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसकी तुलना में भारतीय राष्ट्रभाषा और आधुनिक प्रौद्योगिकी संग उसके तालमेल पर नजर डालें साफ फर्क नजर आता है। भारत अब भी राष्ट्रभाषा से दूर है। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाली ताकतों के सुर भी अब धीमे पड़ते जा रहे हैं। लेकिन चीन अपने आर्थिक उदारीकरण के बावजूद अपनी भाषा की ओर लौटता नजर आ रहा है।

इसके साथ ही चीन के भाषायी आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है। यहां की करीब 80 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी मंदारिन बोल सकती है। चीन में करीब 97.33 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इनमें करीब 95 प्रतिशत से ज़्यादा लोग मानक चीनी अक्षरों का प्रयोग करते हैं। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंटर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते जून तक चीन में एक अरब 12 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र थे। इसी रिपोर्ट के अनुसार, चीन में इंटरनेट इस्तेमाल की दर 79.7 प्रतिशत तक पहुँच गई है। भाषायी कानून में इन आंकड़ों के मद्देनजर सरकारी और पब्लिक सर्विस वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए भी सरकारी नियमों और मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय मानक भाषा का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। इस कानून का लक्ष्य ₹चीनी राष्ट्र के प्रति मजबूत सामुदायिक भावना का विकास ₹और ₹सांस्कृतिक आत्मविश्वास की मज़बूती₹ है। कानून इस बात पर भी ज़ोर देता है कि बोली और लिखी जाने वाली मानक चीनी भाषा के इस्तेमाल का मकसद राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और जातीय एकजुटता बनाना होना चाहिए। यह कानून शिक्षा में भी मानक चीनी भाषा की भूमिका पर ज़ोर देता है। कानून के अनुसार, शिक्षण और पाठ्य सामग्री में मानक मंदारिन ही बुनियादी भाषा होगी। यह भारत की नई शिक्षा नीति जैसा ही है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं के जरिए शिक्षण पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत संस्कृति, पर्यटन और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में सर्विस देने वाले कर्मचारियों के लिए मानक मंदारिन जानना जरूरी होगा। इस कानून में मानक चीनी सीखने या प्रयोग में बाधा डालने पर सजा का प्रावधान भी है। हालांकि पहले उन्हें इसके लिए आगाह किया जाएगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि भारत में भाषा को नकारने को लेकर कोई सजा का प्रावधान नहीं है।

वैसे इस कानून के दुरूपयोग की चिंता भी जताई जा रही है। चीनी संविधान और जातीय स्वायत्तता व्यवस्था के तहत, स्वायत्त क्षेत्रों मसलन, तिब्बत, शिनजियांग, इनर मंगोलिया, गुआंग्शी, निंग्शिया आदि को क्षेत्रीय स्वायत्तता कानूनों के अनुसार, सरकारी कार्यों, शिक्षा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ एक या अधिक स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल का प्रावधान है। लेकिन शी चिनफिंग के शासन में ये प्रावधान कमज़ोर होते गए हैं। इसका असर तिब्बत में दिखता है, जहां कई सालों से चल रहे मातृभाषा आंदोलन और सांस्कृतिक शिक्षा का दमन किया गया। इसकी वजह से वहां निजी स्कूल बंद कर दिए गए और उनके संस्थापक गिरफ्तार कर लिए गए। तिब्बतियों को आशंका है कि इस कानून के तहत उनके खिलाफ दमन का एक और चक्र शुरू हो सकता है।

साल 1994 में फ्रांस ने अपने यहां अंग्रेजी के बिलावजह प्रयोग को कानून के जरिए रोक लगाई थी। अब चीन का अपनी मानक भाषा को स्थापित करने का कानून आया है। यह सब देखते हुए भी भारत की मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर ऐसे कानून का सुझाव देना भी संभव नहीं लगता। लेकिन चीन के इस भाषायी बोध के बहान अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि एक दिन भारत में भी ऐसी सोच जरूर विकसित होगी।

टिप्पणी

भारतीय उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ गया

ये मामला भारत में मोनोपॉली, ड्यूओपॉली और कार्टेल्स बनने की बढ़ती गई शिकायतों की पुष्टि है। इसी का परिणाम है कि उत्पादन संबंधी इनपुट लागत ऊंची बनी रही है, जिससे निवेश और बाजार के विस्तार के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हैं।

कॉम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों टाटा, जिंदल स्टील और सेल ने कई अन्य छोटी कंपनियों के साथ मिल कर कार्टेल (गुट) बनाया और देश में इस्पात की कीमत मिल-जुल कर तय की। 2015 से 2023 के बीच की कई अवधियों में ऐसा किया गया। यानी इन कंपनियों ने आपस में अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नहीं की। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ही उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उचित मूल्य पर मिल सकते हैं। जबकि उत्पादक कंपनियां मिलीभगत कर लें, तो गुणवत्ता पर समझौता करते हुए या मनमानी कीमत वसूलते हुए वे अपना मुनाफा बढ़ाती हैं। इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति रोकने का कानून है। सीसीआई की जांच इस नतीजे पर पहुंची कि स्टील उत्पादक कंपनियों ने संबंधित कानून उल्लंघन किया।

सीसीआई के पास मामला बिल्डरों की अर्जी से पहुंचा, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि नौ स्टील कंपनियों ने मिलीभगत से बाजार में स्टील की उपलब्धता घटाई, ताकि वे महंगी दर पर अपने उत्पाद बेच सकें। सीसीआई ने इन कंपनियों के 56 अधिकारियों को दोषी ठहराया है, जिन पर भारी जुर्माना लगाए जाने की संभावना है। स्पष्टतः ये घटना भारतीय अर्थव्यवस्था में मोनोपॉली (एकाधिकार), ड्यूओपॉली (द्वि-अधिकार) और कार्टेल्स बनने की बढ़ती गई शिकायतों की पुष्टि है। इसी का परिणाम है कि उत्पादन संबंधी इनपुट लागत ऊंची बनी रही है, जिससे निवेश और बाजार के विस्तार के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हैं।

हैरतअंगेज यह है कि ऐसी कंपनियों की सहायता के लिए सरकार भी सहर्ष आगे रही है। बीते हफ्ते ही केंद्र ने डंपिंग रोकने के नाम पर आयातित स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाया। उसके बाद भारतीय स्टील कंपनियों ने अपने उत्पाद की कीमत में 2 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी। यानी भारतीय उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ गया है। मुद्दा यह है कि जो उद्योग घराने अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतों पर अपने मुनाफे को इस तरह तरजीह दे रहे हों, क्या सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए? देश के अंदर वे प्रतिस्पर्धा को रोक रहे हैं, तो उन्हें आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करने में क्या बुराई है?

ब्लॉग

विकसित भारत युवा नेता संवाद: विकसित भारत के लिए युवा नेतृत्व का सशक्तिकरण

डॉ. मनसुख मांडविया

भारत की विकास कथा उन लोगों द्वारा लिखी जाएगी, जो आज इसके विचारों को स्वरुप दे रहे हैं। पूरे देश में, युवा भारतीय इस बारे में गहराई से सोच रहे हैं कि भारत कैसे तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, कैसे बेहतर शासन कर सकता है और किस प्रकार 2047 तक विकसित देश बन सकता है। उनके विचार विश्वविद्यालय परिसरों और समुदायों, स्टार्ट-अप और खेल के मैदानों, कक्षाओं और गांव की बैठकों में उभरकर सामने आ रहे हैं। वास्तविक सवाल अब यह नहीं रहा कि क्या युवाओं के पास योगदान देने के लिए कुछ है, बल्कि यह है कि क्या उनके विचारों को राष्ट्र की दिशा को प्रभावित करने के लिए एक सशक्त मंच दिया जा रहा है। विकसित भारत युवा नेता संवाद (वीबीवाईएलडी) को ऐसा ही मंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आज भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा केवल नीतियों या संस्थाओं से नहीं, बल्कि इसके युवा नागरिकों की कल्पना, दृढ़ विश्वास और साहस से निर्धारित होगी। विशाल युवा शक्ति का यह भंडार केवल जनसांख्यिकीय लाभ नहीं है; यह भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिसंपत्ति है, जो नवाचार को गति देने, लोकतंत्र को मजबूत करने तथा देश को समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में सक्षम है।

भारत की युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को मजबूत उद्देश्य और संभावना से मार्गदर्शन मिलता है। आज का युवा केवल व्यक्तिगत उन्नति से प्रेरणा प्राप्त नहीं करता है; वह जिम्मेदारी उठाने और सार्थक प्रभाव डालने की इच्छा से भी प्रेरित होता है। वे ऐसे रास्तों की खोज करते हैं, जहां उनकी रचनात्मकता, समाधानों में बदल सके, उनकी ऊर्जा नेतृत्व में और उनकी महत्वाकांक्षा सेवा में परिवर्तित हो सके।

युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मुझे विभिन्न पृष्ठभूमियों में - जैसे विश्वविद्यालय परिसरों में, ग्रामीण जिलों में, खेल मैदानों में और युवा नेतृत्व वाली सामुदायिक पहलों में - युवा भारतीयों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। जो चीज़ हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वह यह है कि युवा लोग देश के भविष्य के बारे में कितनी गंभीरता से सोचते हैं। मुझे वह मौका याद है जब मैं ग्रामीण युवा स्वयंसेवकों के एक समूह से मिला, जिन्होंने अपने गाँवों में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का आयोजन किया था। सीमित संसाधनों के बावजूद, दृढ़ विश्वास के साथ, वे शिक्षा और कौशल विकास की कमियों का

स्थानीय रूप से डिज़ाइन किए गए उपायों के माध्यम से समाधान कर रहे थे। उनके विचार व्यावहारिक थे, जमीनी वास्तविकताओं से जुड़े थे और जिम्मेदारी की स्पष्ट भावना से संचालित थे। इस तरह के अनुभव एक सरल सच्चाई की पुष्टि करते हैं: जब युवा लोगों पर भरोसा किया जाता है और उन्हें स्थान दिया जाता है, तो वे केवल भाग नहीं लेते, बल्कि नेतृत्व करते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से आह्वान किया था कि ऐसे एक लाख युवाओं को सार्वजनिक जीवन में लाया जाना चाहिए, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। प्रधानमंत्री की इसी भावना से प्रेरित होकर जनवरी 2025 में 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की परिकल्पना पूरी तरह से नए प्रारूप में की गयी है। प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रही। विकसित भारत चुनौती के माध्यम से 30 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, दो लाख से अधिक निबंध प्रस्तुत किए गए और हजारों युवाओं ने राज्य स्तर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस आयोजन का समापन दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जहां 3,000 युवा नेताओं को प्रधानमंत्री के साथ खुलकर संवाद करने का अवसर मिला, जिन्होंने कई घंटों तक उनके विचार सुने और उन्हें नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया।

संख्याओं से परे, सहभागिता की प्रकृति ने इस संवाद को वास्तव में ऐतिहासिक बनाया। इसने मान्यता दी कि भारत की युवा शक्ति के विचार 2047 के भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। युवा प्रतिभागियों को राष्ट्रीय चुनौतियों के बारे में गंभीरता से सोचने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को साझा उद्देश्य के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे आकांक्षा और क्रियान्वयन के बीच का अंतर समाप्त हो गया।

विकसित भारत युवा नेता संवाद की ताकत केवल इसके पैमाने में नहीं, बल्कि इसके डिज़ाइन में है। विचार, भाषा, संस्कृति और अनुभव की विविधता इस पहल की संरचना में निहित है। शहरी और ग्रामीण भारत के युवा, छात्र और पेशेवर, नवोन्मेषी और जमीनी नेता एक मंच साझा करते हैं। कई स्तरों की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि संवाद और आदान-प्रदान के माध्यम से विचार परिष्कृत होंगे, न कि भौगोलिक, भाषा या पृष्ठभूमि के कारण विचारों को छांट दिया जाएगा। ऐसा करके, संवाद सुनिश्चित करता है कि भाग लेने वाले हर युवा के पास अपनी बात को रखने का अवसर है और उसे विस्तार देने का एक मंच भी है।

भारत के युवाओं ने हमेशा देश के निर्णायक क्षणों में मुख्य भूमिका निभाई है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के संस्थानों के निर्माण तक। हर मोड़ पर, युवा भारतीय साहस, विश्वास और नेतृत्व करने की इच्छा के साथ आगे बढ़े हैं। केवल भागीदारी के लिए नहीं, बल्कि भारत की विकास कहानी के साझा-निर्माण का नेतृत्व करने और इसे गति देने के लिए, आज, राष्ट्र फिर से अपने युवाओं की ओर देख रहा है। 2047 में विकसित भारत का विज़न केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण जिम्मेदारी, तकनीकी मार्गदर्शन और समावेशी विकास की भी मांग करता है। इन जटिल चुनौतियों के लिए ताजा सोच, अनुकूलन क्षमता और अभिनव को अपनाने की योग्यता की आवश्यकता है: ये गुण भारत की युवा शक्ति में प्रबल रूप से मौजूद हैं।

पहली ऐतिहासिक संस्करण की शानदार सफलता के आधार पर, वीबीवाईएलडी2026, जो 9–12 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन से एक ऐसे मंच की ओर निर्णायक छलांग का संकेत देता है जिसकी प्रतिध्वनि वैश्विक है। 'भारत के लिए डिज़ाइन और 'विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी जैसी नई पहलों और अंतरराष्ट्रीय भारतीय युवा प्रवासी की भागीदारी के साथ, संवादों का अब सीमाओं के पार तक प्रसार होता है। फिर भी, इसका मूल उद्देश्य अपरिवर्तित रहता है: युवाओं को साहसपूर्वक सोचने, निडरता से रचना करने और दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना।

इस साल के आयोजन का पैमाना इस महत्वाकांक्षा की गहराई को रेखांकित करता है। विकसित भारत क्विज में 50 लाख से अधिक युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो वीबीवाईएलडी 2026 के चयन का पहला चरण था। यह इसे अपने तरह के सबसे बड़े युवा सहभागिता कार्यक्रमों में से एक बनाता है। चार दिनों के दौरान, देश के हर कोने के प्रतिभागी व्यावहारिक अंतर्दृष्टियों, विचारों और दृष्टिकोणों का लाभ उठाते हुए प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक व्यक्तित्वों के साथ संवाद करेंगे, जो विषयों और भौगोलिक सीमाओं से परे जाते हैं। वास्तव में वीबीवाईएलडी 2026 को अलग बनाने वाली चीज यह है कि यह हमारी युवा शक्ति को केवल बोलने का मौका नहीं देता, बल्कि उन्हें सुने जाने का भी अवसर प्रदान करता है। यह मंच युवा भारतीयों को अपने विचारों, आकांक्षाओं और समाधानों को भारत के प्रधानमंत्री के सामने सीधे प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। 12 जनवरी को, जिसे पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भारत मंडपम में युवाओं के साथ संवाद करेंगे, उनसे सुनेंगे कि वे भविष्य की भारत की कल्पना कैसे करते हैं और किस रूप में उसे आकार देने का इरादा रखते हैं।

जैसे-जैसे भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, देश को उन युवाओं की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है, जिनमें बड़े सपने देखने का साहस है और विचारों को सार्थक कार्य में बदलने का दृढ़ संकल्प है। संवाद के लिए एक मंच से कहीं अधिक, विकसित भारत युवा नेता संवाद एक अभियान है, जो भारतीय युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने, राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने और विकसित भारत के साथ अपनी आकांक्षाओं को जोड़ने का आह्वान करता है। विकसित भारत का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, जिनमें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास और सेवा करने की प्रतिबद्धता है। भारत के युवा तैयार हैं। राष्ट्र को उनके साथ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं)

बाराबंकी में रालोद प्रदेश सचिव को भतीजे ने मारी गोली, हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ में चल रहा अफसर अली का इलाज

घायल अफसर अली को छर्रे लगे हैं और उनका इलाज लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। गांव में घटना के बाद से तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में बीते सोमवार देर रात राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के प्रदेश सचिव अफसर अली को गोली मार दी गई। आरोप है कि संपत्ति बंटवारे के विवाद में उनके सगे भतीजे ने तमंचे से फायर किया। गोली लगने से अफसर अली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ में भर्ती कराया गया।

कुर्सी थाना क्षेत्र के लोहराहार गांव निवासी 50 वर्षीय अफसर अली वर्तमान में परिवार सहित लखनऊ में रहते हैं। वह सोमवार को पड़ोस के एक गांव में परिचित व्यक्ति के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। अंतिम संस्कार के बाद वह अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां एक दुकान के पास जल रही आग के पास कुछ ग्रामीणों के साथ बैठकर गांव के हालचाल पर बातचीत कर रहे थे।

आरोपी भतीजा गिरफ्तार

इसी दौरान उनके सगे भतीजे उबैद ने अचानक तमंचे से फायर कर दिया। गोली के छर्रे अफसर अली के सीने में लगे, जिससे वह मौके पर ही घायल हो गए। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने उबैद को गिरफ्तार कर लिया है।

गांव में पुलिस फोर्स तैनात

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सीओ फतेहपुर जगतराम कनौजिया ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। भतीजे द्वारा गोली मारने की बात सामने आई है।

कायस्थ समाज ने मनाई विवेकानंद, महेश योगी जयंती

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। नगर के एक होटल में कायस्थ समाज के संगठनों ने स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी की जयंती मनाई। को श्री चित्रगुप्त भगवान अखाड़ा परिषद के स्थापना दिवस पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया।कायस्थ महासभा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव साधु ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के ज्ञान का परचम लहराया था। आज उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। कायस्थ एकता मंच के जिलाध्यक्ष दयाशंकर निगम ,कायस्थ संघ अंतर्राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष अजय वर्मा ने युवाओं से विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया।राष्ट्रीय महासचिव राजेश श्रीवास्तव श्बच्चा भईया एडवोकेट ने महर्षि महेश योगी के प्रेरणादायक सफर पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे महेश प्रसाद वर्मा शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी द्वारा बाल ब्रह्मचारीश की उपाधि पाकर महर्षि महेश योगी बने और समाज में बड़ा योगदान दिया। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष डॉ. उमाकांत श्रीवास्तव प्रिंसिपल ने बताया कि महर्षि योगी ने 1959 में अमेरिका से अपनी विश्व यात्रा शुरू की थी। उनके दर्शन का मूल आधार था कि जीवन परमानंद से भरपूर है और मनुष्य का जन्म इसका आनंद उठाने के लिए हुआ है।कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव , प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ,बजरंग प्रसाद श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि आज के आयोजन में दिखाई देने वाली एकता ही महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि है।

बेटी को मामा के साथ भेजा, फिर ससुराल वालों पर लगा दिया दहेज के लिए हत्या का आरोप... 6 महीने बाद मुंबई से जिंदा मिली लड़की

आर्यावर्त संवाददाता

श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक परिवार ने पहले अपनी बेटी को गायब कर दिया और फिर उसके ससुराल वालों पर उसकी हत्या का आरोप लगा दिया। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो परिजन ने कोर्ट का रुख किया। अब जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिस लड़की की हत्या का आरोप परिजन ससुराल वालों पर लगा रहे थे। वह जिंदा निकली।

ये मामला श्रावस्ती के थाना मल्हीपुर के लक्ष्मणपुर गंगापुर का है, जहां रहने वाली दीपा की शादी करीब 4 साल पहले इसी थाना क्षेत्र के ओरी पुरवा गांव में हंसराज के साथ हुई थी। दीपा और हंसराज की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन अगस्त 2025 में दीपा की मां मायावती ने एक साजिश रची और अपने भाई यानी दीपा के मामा के साथ दीपा को उसके ससुराल से गायब करा दिया। इधर दीपा के ससुराल में दीपा के न मिलने से हड़कंप मच गया। दीपा के ससुराल वालों ने उसकी काफी तलाश की।

ससुराल वालों पर कर दिया हत्या का केस

लेकिन जब दीपा ससुराल वालों काफी खोजबीन के बावजूद नहीं मिली तो मायके वालों को फोन कर जानकारी दी, जिसका मायावती को पहले से इंतजार था। मायावती ने फौरन ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इस पर मायावती ने कोर्ट की शरण ली और दीपा के पति हंसराज के साथ पूरे परिवार के 6 लोगों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। अब पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझाना शुरू किया और दीपा के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन मुंबई के पुणे में मिली।

इसके बाद जब मल्हीपुर पुलिस मुंबई पहुंची तो लड़की को जिंदा बरामद कर लिया गया। अपनी कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। अब दीपा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं लड़की की मां मायावती अब इस मामले पर यू टर्न लेती नजर आ रही है। अब वह कर रही है हमें इस मामले पर कुछ जानकारी नहीं थी, जब हमें फंसाने की कोशिश की गई तो हमने भी उन्हें फंसाया, लड़की किसके साथ गई है यह मुझे नहीं पता।

6 महीने बाद मुंबई से जिंदा मिली दीपा

लड़की के पिता गोली ने कहा कि जब दीपा गायब हुई तो लड़की के पति हंसराज ने उन्हें फोन करके बताया कि लड़की कहीं गायब है। हमने दहेज हत्या का कोई मामला दर्ज नहीं कराया। हमने लड़की की गुमशुदगी की बात कही। वहीं हंसराज की मां चमेली ने कहा कि करीबन 6 महीने पहले दीपा शौच के बहाने सुबह 4 बजे अपने मामा के साथ गायब हो गई, जब घर में दीपा नहीं मिली तो हमने काफी तलाश की, फिर उसके मायके वालों को जानकारी दी, हमने कभी भी दीपा को किसी भी दहेज या अन्य मामले को लेकर प्रताड़ित नहीं किया। यह हम पर झूठा आरोप है। आज पुलिस ने उसे जिंदा बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।

डिजिटल लाइब्रेरी में युवक फांसी पर झूला

जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र के बनीडीह गांव निवासी 22 वर्षीय शैलेश यादव पुत्र आशाराम ने सधीरनगंज बाजार स्थित अपनी डिजिटल लाइब्रेरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार आधी रात की बताई जा रही है। जैसे ही युवक को फंदे से लटका देखा गया, पूरे बाजार और गांव में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शैलेश प्रतिदिन की तरह अपनी डिजिटल लाइब्रेरी में ही सो रहा था। देर रात जब कुछ लोगों की नजर अंदर पड़े शव पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया। आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। तत्काल परिजनों को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

परिवार से कर रही थी बात, फोन कटा भी नहीं और लगा ली फांसी... एएमयू में इंजीनियरिंग की छात्रा ने क्यों दी जान?

आर्यावर्त संवाददाता

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरोजिनी नायडू हॉल में 20 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान 20 वर्षीय इंशाह फातिमा के रूप में हुई है, जो आजमगढ़ की रहने वाली थीं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रही थी। फातिमा फाइनल ईयर की छात्रा थीं। बताया जा रहा है कि छात्रा ने अपने किसी परिजन से बात करते हुए फांसी लगाई।

फातिमा इंशाह ने SN हॉल में अपने कमरे में फांसी लगाई, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वह अपने परिवार के किसी परिजन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं। हॉल स्टाफ और अन्य छात्राओं को जानकारी मिलते ही तुरंत एक्शन लिया गया। दरवाजा खुलवाकर उन्हें बाहर निकाला गया। फिर तुरंत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के

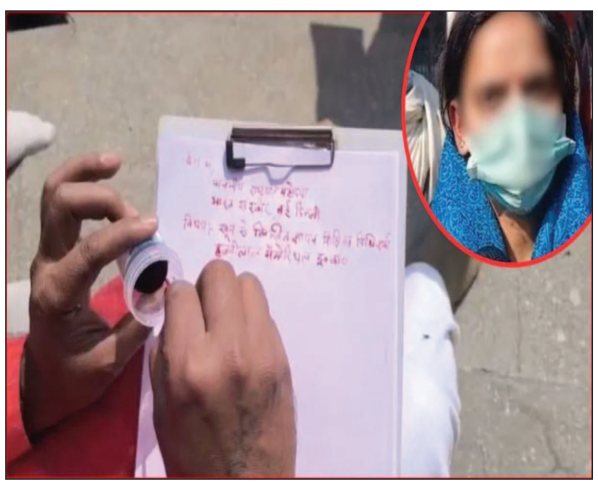

आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में यह घटना हुई। इसलिए स्थानीय पुलिस जांच में जुटी हुई है। AMU प्रशासन और प्रॉक्टोरियल टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। AMU प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉ. वसीम अली ने घटना की पुष्टि की और बताया कि सूचना मिलते ही टीम तुरंत पहुंची, छात्रा को बिना देर किए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हॉल स्टाफ और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून भी छात्रा का हाल जानने मेडिकल कॉलेज पहुंची थीं।

पुलिस कर रही मामले की जांच

आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। परिवार, दोस्तों और अन्य छात्राओं से पूछताछ जारी है। पढ़ाई का दबाव, व्यक्तिगत कारण और अन्य मुद्दे जांच के दायरे में हैं। AMU इंतजामिया और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसमें कमरे की जांच, मोबाइल, डायरी आदि की जांच शामिल है। यह घटना AMU कैंपस

मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में भीड़

जौनपुर। मकर संक्रांति पर्व को लेकर मंगलवार को विशेष रौनक देखने को मिली। सुबह से ही बाजार में भारी भीड़ उमड़ पड़ी।लोगों ने पूजा-पाठ के लिए आवश्यक सामग्री जैसे तिल, गुड़, खिचड़ी का सामान, दान-पुण्य हेतु वस्त्र, बर्तन, फल, मिठाई और घरेलू उपयोग की चीजें खरीदीं। विशेष रूप से तिलकुट, गुड़ की रेवड़ी, चूड़ा, दही और सब्जियों की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गईं। दुकानदारों ने भी पर्व को देखते हुए अपने प्रतिष्ठानों को सजाया था और ग्राहकों के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था की थी। ग्रामीणों में पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। महिलाओं ने घरेलू पूजन सामग्री खरीदी, जबकि युवाओं और बच्चों ने बाजार में मेले जैसा माहौल बना दिया। बाजार में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी सतर्क दिखी। मकर संक्रांति के प्रति लोगों में आस्था और परंपरा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। बाजार की इस चहल-पहल से व्यापारियों में भी खुशी का माहौल था।

बागपत की महिला टीचर ने खून से लिखा लेटर, फिर डीएम को सौंपा, राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु... आखिर क्या हुआ ऐसा?

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक बेहद संवेदनशील और विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला टीचर ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए खून से लिखा ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर शिक्षिका ने महामहिम राष्ट्रपति से अपने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। इस घटना के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।

मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली नेहा (काल्पनिक नाम) का चयन वर्ष 2022 में हुआ था और वह बागपत के हजारी लाल इंटर कॉलेज में तैनात हैं। सोमवार को शिक्षिका अपने परिवार और सर्वसमाज के लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचीं। नेहा का आरोप है कि जब से उनकी तैनाती हुई है,

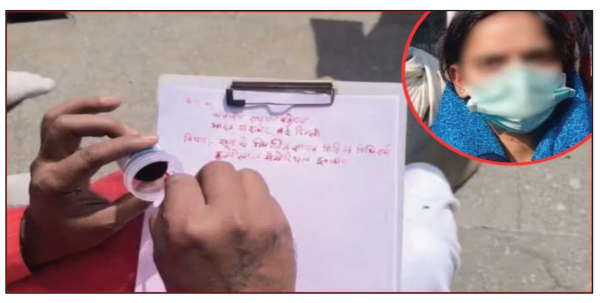

कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल और वर्तमान प्रबंधक राजेंद्र सिंह भाटी उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

खून से लिखा पत्र और सामूहिक धरना

न्याय की मांग को लेकर शिक्षिका के समर्थन में भारी संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान विरोध का एक अनोखा और डरावना तरीका अपनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपना खून एकत्र किया और उससे महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखा। शिक्षिका ने पत्र में साफ तौर पर कहा कि वो इस प्रताड़ना को सहने की शक्ति खो चुकी हैं और अब परिवार सहित मौत चाहती हैं।

प्रशासनिक उदासीनता का आरोप

टीचर नेहा ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रशासनिक उदासीनता ने उन्हें यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर किया है।

जांच का मिला आश्वासन

मामले की गंभीरता को देखते हुए मानवाधिकार संगठनों ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए शिक्षिका को पूरे मामले की गहराई से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

गेहूं की फसल चौपट कर रहे नीलगाय

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मछलीशहर तहसील क्षेत्र के किसानों की गेहूं की फसल पर नीलगाय आफत बने हुए हैं। किसान रात जाग करके गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे हैं। बसुही नदी किनारे बसे भटेवरा,बामी, ऊंचडीह, अदारी,कठार, सेमरहो, रामगढ़,तिलौरा, अलापुर के किसान शाम होते ही टार्च और लाठी लेकर गेहूं के खेतों की ओर निकल जाते हैं और रात के दस ग्यारह बजे तक नदी किनारे ही अलाव जलाकर रहते हैं। बामी गांव के किसान शैलेन्द्र बताते हैं कि नीलगाय जितना गेहूं की फसल को चरते नहीं हैं उससे ज्यादा सींचे गये खेतों में पैरों से कुचलकर गेहूं की फसल नष्ट कर रहे हैं।चरी फसल तो पनप जायेगी लेकिन पैरों से कुचली फसल कीचड़ में खत्म हो रहा है।

नाले में गिरी 6 साल की बच्ची, सौतेली मां ने कमरे में बंद कर डंडे से इतना पीटा... मासूम की हो गई मौत

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से कलयुगी मां ने अपनी ही बच्ची को मार डाला। 6 साल की मासूम ने नाली के पानी से कपड़े क्या गंदे कर लिए, सौतेली मां ने गुस्से में मासूम को इतना पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। सौतेली मां ने सोमवार को बच्ची को कमरे में बंद कर दिया था। फिर लगभग आधा घंटे तक डंडे से मारती रही। डंडे की मार से मासूम के हाथ पैर टूट गए और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। मासूम की कब मौत हो गई, किसी को पता ही नहीं चला।

मामला वेब सिटी थाना क्षेत्र के डासना की है। यहां पर सौतेली मां ने 6 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला, क्योंकि वो खेलते-खेलते नाले में गिर गई थी। इससे उसके कपड़े गंदे हो गए थे। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घर

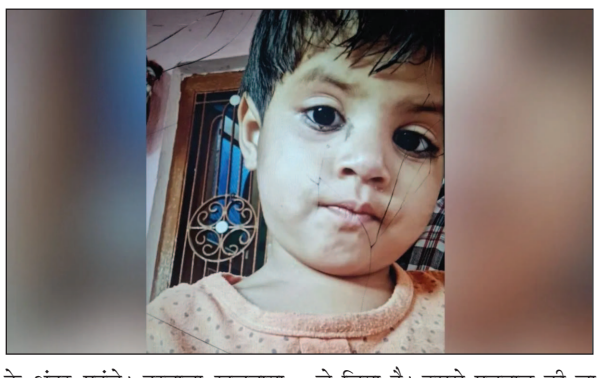

के अंदर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया तो बच्ची को छोड़कर उसकी सौतेली मां भागने लगी। मगर पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस को सूचना दे दी।

सूचना पर वेव सिटी थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे और मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

दो साल पहले अकरम ने की थी दूसरी शादी

आरोपी महिला का नाम निशा है, जो मसूरी थाना क्षेत्र के डसना में अपने पति अकरम के साथ रह रही थी। महिला का पति अकरम मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। लगभग 4 साल पहले अकरम की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। पहली पत्नी से बेटी शिफा पैदा हुई थी। 2 साल पहले अकरम की दूसरी शादी निशा से हुई थी। घटना वाले दिन सोमवार को अकरम रोजाना की तरह मजदूरी के लिए घर से बाहर गया था। उसकी गैर मौजूदगी में सौतेली मां निशा ने 6 साल की शिफा को कमरे में बंद करके उसकी जमकर पिटाई कर डाली।

एसीपी ने महिला को लिया हिरासत में

जानकारी के मुताबिक पहले उसने बच्ची के लात और थप्पड़ मारे उसके बाद डंडे से बार-बार वार किया लगातार होती पिटाई से मासूम शिफा की मौत हो गई। घटना की जानकारी जब वेब सिटी की एसीपी प्रिया श्रीपाल को पता चली तो वो भी मौके पर पहुंचीं। आरोपी महिला को उन्होंने हिरासत में ले लिया। पुलिस अब आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

बच्ची ने पापा से की थी मां की शिकायत

बच्ची के पिता अकरम से मिली जानकारी के मुताबिक, बच्ची ने उससे कई बार अपनी सौतेली माता की शिकायत की थी। उसने पिता को बताया था कि सौतेली मां उसे बहुत मारती है। अकरम बोला- मैंने बीवी को समझाया था और दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत भी दी थी।

एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि पुलिस ने बच्चों की मां और पिता दोनों को हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी सौतेली मां ने मासूम की हत्या करने की बात कबूल कर ली है।

सम्पादक मण्डल ने शासन को भेजा 3 सूत्रीय मांग पत्र

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पत्रकार सुरक्षा कानून, सम्पादकों को आयुष्मान कार्ड एवं सरकारी विभागों द्वारा जारी विज्ञापनों को रोस्टरवार समाचार पत्रों को दिये जाने के संदर्भ में सम्पादक मण्डल उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई द्वारा मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट इन्द्रनन्दन सिंह को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष राकेशकान्त पाण्डेय के नेतृत्व में दर्जनों सम्पादकों ने जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष ने कहा कि समाचार संकलन के साथ सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के बाबत सम्पादको/पत्रकारों/छायाकारों पर आये दिन हमला हो रहे हैं। इसको देखते हुये पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाय, ताकि हमलावरों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही हो जिससे भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो सके। निजी संसाधनों से समाज के प्रहरी की भूमिका निभाने वाले समाचार पत्रों के सम्पादकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाय। इसके लिये अन्त्योदय कार्ड, 70 वर्ष की अवस्था एवं राशन कार्ड पर 6 सदस्यों वाली शर्त न लागू हो। सरकारी विभागों द्वारा जारी होने वाले विज्ञापनों को सूचना विभाग या जिला प्रशासन के माध्यम से रोस्टरवार दिया जाय, ताकि समस्त समाचार पत्रों को इसका लाभ मिल सके। महासचिव डा. नौशाद अली , आदर्श कुमार, शम्भू सिंह, डा. ब्रजेश यदुवंशी, पूर्व अध्यक्ष रामजी जायसवाल, डा. प्रमोद वाचस्पति, मंगला प्रसाद तिवारी, महेन्द्र प्रजापति, विरेन्द्र मिश्र विराट, छोटे लाल सिंह, शब्बीर हैदर, प्रदीप पाण्डेय, मकसूद सिद्दीकी, एमए सिद्दीकी, आदि मौजूद रहे।

सर्दियों में वेट रहेगा कंट्रोल, मिड क्रेविंग के लिए ये हैं हेल्दी स्नैक्स

सर्दी के दिनों में लोगों को वजन बढ़ने की चिंता सताने लगती है। ऐसे में मिड क्रेविंग के लिए अपनी डाइट में कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन रिच स्नैक्स शामिल कर सकते हैं। इससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और शरीर को अंदर से गर्माहट भी मिलेगी।

वेजिटेबल

अनहेल्दी फूड खाना आज के वक्त में बढ़ते वजन की एक बड़ी वजह है। ज्यादातर लोग मिड क्रेविंग में हेल्दी स्नैक्स की बजाय चिप्स, कुकीज, नमकीन, जैसी चीजें ही खाते हैं, जिनमें ट्रांस फैट के साथ ही सोडियम और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ने के साथ ही कई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। सर्दी के दिनों में रूटीन भी थोड़ा सुस्त हो जाता है, ज्यादातर लोग इस मौसम में घर पर भी गाजर का हलवा, नाश्ते में आलू के पराठे, कचौड़ी, समोसे जैसी चीजें खाते हैं, जिससे वेट बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर ऐसे में स्नैक्स भी अनहेल्दी हो तो दिक्कत ज्यादा हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ हेल्दी स्नैक्स जो वेट कंट्रोल में हेल्प फुल रहते हैं।

सर्दी के दिनों में लोगों को वेट बढ़ने का ज्यादा डर रहता है, क्योंकि तापमान में गिरावट आने के साथ ही रूटीन थोड़ा सुस्त हो जाता है। ऐसे में हेल्दी फूड्स लेना जरूरी है ताकि वजन न बढ़े। जान लेते हैं ऐसे ही स्नैक्स के बारे में जो आपकी मिड क्रेविंग को शांत करेंगे और वजन भी कंट्रोल में रहेगा।

रोस्टेड मखाना और मूंगफली

सुबह अगर हेल्दी नाश्ता न किया जाए या फिर ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया जाए तो मिड क्रेविंग ज्यादा होती है। इस वजह से लोग अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं, इसलिए रोजाना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ता करना चाहिए। फिलहाल लंच और ब्रेकफास्ट या फिर लंच और डिनर के बीच के टाइम के लिए अपने साथ आप रोस्टेड मखाना और मूंगफली का मिक्स रख सकते हैं। इसमें हल्का सा नमक डालें। ये टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी रहता है।

सूप है बेस्ट ऑप्शन

अगर आप घर पर हैं तो सर्दियों में मिड क्रेविंग के लिए वेजिटेबल

सूप पीना सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इससे बनने में ज्यादा टाइम, मसाले और तेल भी नहीं लगता है। इससे शरीर को कई न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इसलिए सूप वेट कंट्रोल करने के लिए एक बढ़िया कंफर्ट फूड है।

डार्क चॉकलेट कोटेड नट्स

हेल्दी स्नैक्स की बात करें तो आप अपने साथ डार्क चॉकलेट कोटिंग वाले बादाम या फिर पिस्ता साथ में रखें। इसमें शुगर भी नहीं होता है। ये वेट कंट्रोल करने के साथ ही दिल के साथ ही दिमाग के लिए भी हेल्दी स्नैक है।

वेट कंट्रोल के लिए ये भी है बढ़िया स्नैक

अगर आपको मिड क्रेविंग में क्रिस्पी चीजें खाना पसंद है तो आप रोस्टेड चना को डाइट में जगह दें। इससे आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलेगा और इसमें कोई एक्स्ट्रा फैट भी नहीं होता है। हालांकि ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप रोस्टेड चना खा रहे हैं तो पानी अच्छी मात्रा में पिएं।

सीड्स और नट्स का मिक्सचर

हेल्दी स्नैक्स की बात आए तो सर्दी में आप अपने साथ सीड्स जैसे अलसी, सूरजमुखी के बीज, चिया सीड्स। नट्स में बादाम, अखरोट, पिस्ता को हल्का रोस्ट कर लें और फिर इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें। ये मिक्सचर शरीर को गर्माहट भी देगा और वेट कंट्रोल में भी हेल्प फुल रहेगा।

इस नए साल में चमकेगा चेहरा, स्किन केयर के ये गोल्डन रूल फॉलो करने का लें संकल्प

नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ लोग कई रह के रेज्युलेशन लेते हैं जैसे फिट रहना, पैसे इन्वेस्ट करना, बुक्स पढ़ना, नई स्किल सीखना। हालांकि इसी के साथ हर कोई चाहता है कि बिना मेकअप के भी उसका चेहरा ग्लो करे। इसके लिए बहुत सारे लोग लोग होम रेमेडीज ट्राई करने से लेकर सैलून में भी अच्छे-खासे पैसे खर्च करते हैं और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी मार्केट में भरमार है। साल 2024 में आप अपनी स्किन को हेल्दी और नेचुरल ग्लोइंग बनाने का संकल्प भी ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट का यूज करें या फिर होम रेमेडीज इस्तेमाल करें, बल्कि जरूरी ये है कि अपनी त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए स्किन केयर के रूल फॉलो करें।

त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप त्वचा की देखभाल सही तरीके से करें। नेचुरल ग्लोइंग स्किन आपको बढ़ती उम्र में भी यंग दिखाने का काम करती है। अगर इस नई साल में आप स्किन ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो कुछ गोल्डन रूल्स को जरूरी फॉलो करना चाहिए। चलिए विस्तार से जान लेते हैं।

स्किनहाइड्रेशन है सबसे जरूरी

त्वचा को हेल्दी, ग्लोइंग बनाए रखने और झुर्रियों-फाइन लाइन की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि त्वचा में नमी बनी रहे। स्किन हाइड्रेशन के लिए कोई ऐसा मॉश्चराइजर रोजाना अप्लाई करें जो त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेट रखे। इसके अलावा पानी भरपूर मात्रा में पीते रहें।

सनस्क्रीन न करें स्किप

ज्यादातर भारतीय सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, लेकिन त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए रोजाना सनस्क्रीन अप्लाई करना जरूरी है। इससे यूवी किरणों से बचाव होता है और स्किन डैमेज नहीं होती, जिससे प्रीमेच्योर एजिंग (उम्र से पहले झुर्रियां और महीन लाइनें होना) का डर नहीं रहता है।

फेस योगा करें

त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ मिनट का फेस योगा करना चाहिए। इससे बढ़ती उम्र में भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फेस योगा करने से जॉ लाइन अच्छी होती है। इससे स्किन की पफिनेस भी कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप फिश पोज, स्माइल फिश फेस, नेसोलेबियल फोल्ड आदि कर सकते हैं।

डबल क्लींजिंग करें

डबल क्लींजिंग का मतलब होता है कि त्वचा पर जमा धूल-मिट्टी के अलावा पोर्स में जमा अशुद्धियां और मेकअप के कण भी साफ हो जाएं। इससे एक्सट्रा ऑयल त्वचा से नहीं निकलता है और एक्ने होने की संभावना कम होती है। फेस वॉश करने के अलावा क्लींजिंग ऑयल या क्लींजिंग बाम से चेहरे पर मसाज करनी चाहिए, इसके बाद गर्म पानी में एक मुलायम कपड़ा भिगोकर निचोड़ लें और इससे चेहरे को साफ करें। इसके बाद फेस वॉश करें।

हर हफ्ते करें एक्सफोलिएट

त्वचा को हर हफ्ते एक्सफोलिएट करना चाहिए। इसके लिए अपनी स्किन टाइप के मुताबिक कोई स्क्रब ले सकते हैं और 5 मिनट तक उंगलियों से जेंटल मसाज करके चेहरा धो लें। इससे त्वचा गहराई से साफ होगी और डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होते हैं। एक्सफोलिएशन करने से वाइट और ब्लैक हेड्स कम होते हैं साथ ही स्किन का टेक्सचर भी सुधरता है।

मेघालय जा रहे हैं तो यहां के इन खूबसूरत गांवों में घूमना न भूलें

मेघालय का हर गांव अपनी नैचुरल ब्यूटी और कल्चर के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां के गांव न केवल साफ–सफाई और हरियाली के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यहां की लाइफस्टाइल भी बेहद आम लेकिन खास होती है। इसलिए जब भी आप मेघायल जाएं तो वहां के गांव की सैर करना ना भूलें।

मेघालय भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहां की हरी-भरी वादियां, ऊंचे-ऊंचे पहाड़, झरने, और शांत नदियां किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। लेकिन मेघालय की असली पहचान उसके खूबसूरत गांवों में छिपी है। ये गांव न केवल अपनी नैचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहां की साफ-सफाई और स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर आप शहरी जीवन की भागदौड़ और तनाव से थक गए हैं, तो मेघालय के गांव आपके लिए एक परफेक्ट गेटवे साबित हो सकते हैं।

यहां का शांत माहौल, ताजी हवा, और हरियाली आपको सुकून का अहसास कराएगी। इन गांवों में आपको नेचक के साथ-साथ यहां के अनोखे रीति-रिवाज, ट्रेडिशनल फूड और सिंपल लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मेघालय के गांवों में लिविंग रूट ब्रिज, कांच जैसी साफ नदियां, और खूबसूरत घाटियां हैं, जो हर टूरिस्ट का दिल जीत लेती हैं। अगर आप भी मेघालय की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यहां के इन खास गांवों की सैर करना बिल्कुल न भूलें। ये गांव न सिर्फ आपकी जर्नी को खास बनाएंगे, बल्कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस देंगे जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा।

मावलिननोंग

मावलिननोंग एशिया का सबसे साफ-सुथरे गांव में से एक है। ये गांव हरियाली से घिरा हुआ और इको फ्रेंडी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। यहां लिविंग रूट ब्रिज और बांस के बने सुंदर घर देखने लायक हैं। इस गांव को "गॉड्स ओन गार्डन" के नाम से भी जाना जाता है। यहां आएं तो गांव की गलियों में घूमें और यहां के लोकल कल्चर का एक्सपीरियंस लें। इस गांव के आसपास के झरने और वॉचटावर से खूबसूरत नजारे आप भूल नहीं पाएंगे।

शनोंगपडेंग

ये गांव उमंगोट नदी के पास स्थित है। इस नदी को एशिया की सबसे साफ नदी माना जाता है। इस नदी का पानी एक दम क्रिस्टल की तरह क्लियर हैं, जिसमें नाव चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इस गांव में बोटिंग, स्विमिंग, और कैम्पिंग करने का अपना ही अलग मजा है। साथ ही आप यहां नदी के पास बैठकर सुकून भरे पल भी बिता सकते हैं।

रिवाई

मेघालय का रिवाई गांव एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत और अनोखा गांव है, जो अपनी नैचुरल ब्यूटी और "लिविंग रूट ब्रिज" के लिए मशहूर है। ये गांव चेरापूंजी के पास स्थित है और मावलिननोंग गांव के करीब है। रिवाई गांव शांति और हरियाली का बेहतरीन उदाहरण है। यहां का माहौल इतना शांत और स्वच्छ है कि आप खुद को नेचर के बिल्कुल करीब महसूस करेंगे। नेचर लवर और ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए ये गांव एक दम परफेक्ट है।

लैतलम

मेघालय का लैतलम गांव नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। खासी हिल्स के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों और हरी-भरी घाटियों के बीच बसा ये गांव अपने अद्भुत नजारों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। लैतलम का मतलब ही "दुनिया का अंत" होता है, और यहां से देखने पर सच में ऐसा लगता है कि आप दुनिया के किनारे खड़े हैं। लैतलम गांव एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी खास है। यहां के वॉटरफॉल्स देखने लायक हैं।

दावकी

ये गांव मेघालय के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। ये गांव भारत-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है और अपनी साफ-सुथरी नदियों, हरियाली, और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। दावकी की उमंगोट नदी दुनिया की सबसे साफ नदियों में से एक मानी जाती है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि नावें पानी के ऊपर तैरती हुई सी लगती हैं। दावकी के आसपास कई खूबसूरत झरने और हरे-भरे जंगल हैं, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं।

मेघायल के ये गांव देखने लायक हैं। आप जब भी मेघायल की ट्रिप प्लान करें तो इन गांव को घूमना बिल्कुल ना भूलें। ये गांव आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगे। लेकिन याद रहें की बरसात के मौसम में यहां जाने से थोड़ा परहेज करें।

क्रिप्टो निवेशकों के लिए बड़ी खबर : अकाउंट खोलना अब होगा मुश्किल, सरकार ने सख्त किए नियम

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं या भविष्य में अकाउंट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल एसेट्स के तेजी से बढ़ते प्रभाव के साथ निवेशकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग और अवैध लेनदेन जैसी गतिविधियों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नई सुरक्षा और पहचान संबंधी नियम लागू किए हैं।

क्रिप्टो अकाउंट खोलना अब आसान नहीं

वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (स्नढ्ढ) ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (रूरूरु) और केवाईसी (यङ्घष्ट) दिशानिर्देश जारी किए हैं। 8 जनवरी को जारी इन नियमों के तहत अब केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पर्याप्त नहीं होगा। यूजर्स को अकाउंट खोलने के लिए कई अतिरिक्त सत्यापन स्टेप्स पूरे करने होंगे।

लाइव सेल्फी और जियो-टैगिंग अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, अकाउंट बनाते समय यूजर को लाइव सेल्फी देनी होगी। इसमें सिर हिलाने या आंख झपकाने जैसे इशारों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति असली है, न कि किसी फोटो या डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही जियो-टैगिंग भी जरूरी होगी, जिसमें यूजर की लोकेशन, तारीख, समय और आईपी एड्रेस रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान और संदिग्ध गतिविधियों को रोकना है।

पहचान और बैंक वेरिफिकेशन मजबूत

अब अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड के अलावा पासपोर्ट, आधार या वोटर आईडी में से किसी एक पहचान पत्र की जरूरत होगी। इसके अलावा ई-मेल और मोबाइल नंबर का ह्ल्ज्क्क वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। पेनी-ड्रॉप प्रक्रिया भी लागू की गई है, जिसके तहत बैंक खाते की पुष्टि के लिए एक रुपये का ट्रांजैक्शन किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि डिजिटल एसेट्स का गलत इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। नए नियमों का मकसद क्रिप्टो इकोसिस्टम को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।

गेल ने पीएनजीआरबी के नॉनस्टॉप ज़िंदगी अभियान से जुड़कर राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 को दिया समर्थन

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 के तहत देशव्यापी नॉनस्टॉपज़िंदगी अभियान में भागीदारी की है। यह अभियान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूरे देश में पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस और संपीड़ति प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देना है। यह अभियान प्राकृतिक गैस से जुड़े सभी प्रमुख पक्षों की एकजुटता को दर्शाता है, जो घरों, व्यापार, उद्योग और परिवहन क्षेत्र के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर ऊर्जा समाधान अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 का आयोजन 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक किया जा रहा है। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक देश की ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तक बढ़ाई जानी है और भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है। इस दिशा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने ₹एक देश, एक ग्रिड, एक शुल्क₹ के सिद्धांत पर आधारित एकीकृत शुल्क व्यवस्था लागू की है, जिससे पूरे देश में गैस परिवहन का एक समान और किफायती ढांचा तैयार हो सके।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस, संपीड़ति प्राकृतिक गैस और नगर गैस वितरण व्यवस्था के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और मांग पैदा करना है। इसके माध्यम से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में गैस के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ति प्राकृतिक गैस को एक बेहतर ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

अभियान में उपभोक्ता को केंद्र में रखते हुए पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस और संपीड़ति प्राकृतिक गैस के लाभों को प्रमुखता से बताया गया है। इनमें अधिक सुरक्षा, चौबीसों घंटे भरोसेमंद आपूर्ति, उपयोग में आसानी और खर्च में बचत जैसे फायदे शामिल हैं। यह संदेश रोजमर्रा की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक गैस को भविष्य के लिए उपयुक्त ईंधन के रूप में प्रस्तुत करता है।

अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए इस अभियान में डिजिटल, ऑफलाइन और जमीनी स्तर पर गतिविधियों का समन्वय किया गया है। इससे लोगों से लगातार संपर्क बना रहता है और अभियान की पहचान मजबूत होती है। नगर गैस वितरण कंपनियों को एक समान रचनात्मक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे पूरे देश में एक जैसा संदेश पहुंचे और बेहतर परिणाम मिल सकें।

अभियान की रचनात्मक योजना चार प्रमुख वर्गों पर केंद्रित है- घरेलू उपभोक्ता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाइयां और वाहन उपयोगकर्ता। इसके तहत दूरदर्शन विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, पर्चे, सूचना केंद्र और पत्रिकाओं में विज्ञापन जैसे माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

डिजिटल और सामाजिक माध्यमों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए सामाजिक मंचों पर संदेश, छोटे चलित चित्र, प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से प्रचार और विभिन्न मंचों के लिए तैयार किए गए वीडियो शामिल हैं। इसके साथ ही आवासीय संघों के लिए विशेष सामग्री और चलित वाहनों के माध्यम से प्रचार कर समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। त्योहारों और स्थानीय संस्कृति से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों से बेहतर जुड़ाव बनाया जा रहा है।

नॉनस्टॉपज़िंदगी अभियान में भाग लेकर गेल ने स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और भारत को टिकाऊ व गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है।

गेल के बारे में

गेल एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस परिवहन और वितरण कंपनी है। कंपनी देशभर में गैस पाइपलाइन, प्रसंस्करण संयंत्र और पेट्रो रसायन संयंत्र संचालित करती है। इसके साथ ही गेल तेल और गैस खोज तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस पुनर्गैसीकरण परियोजनाओं में भी सक्रिय है। गेल प्राकृतिक गैस, पेट्रो रसायन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न पहलों के माध्यम से देश के ऊर्जा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंतजार खत्म ! किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2000 रुपये, मिल सकती है 'डबल' खुशखबरी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब सिर्फ एक सरकारी सहायता नहीं, बल्कि खेती की रीढ़ बन चुकी है। केंद्र सरकार अब तक इस योजना के तहत 21 किस्तें जारी कर चुकी है और अब किसानों की निगाहें 22वीं किस्त पर टिकी हुई हैं।

सरकारी नियमों के अनुसार पीएम किसान योजना की राशि साल में तीन बार—अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च के बीच—किसानों के खातों में भेजी जाती है। पिछली किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी, ऐसे में 22वीं किस्त का समय दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच बनता है। प्रशासनिक तैयारियों और पुराने ट्रेंड को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार मार्च 2026 या अप्रैल 2026 की शुरुआत में अगली किस्त जारी कर सकती है।

बजट में मिल सकती है किसानों को खुशखबरी

देश इस समय 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट का इंतजार कर रहा है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में मिलती है। बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बजट में सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जिससे किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

किस्त से पहले पूरा करें ई-केवाईसी

हर बार की तरह इस बार भी कई किसानों के खातों में पैसा अटकने की आशंका है। इसकी सबसे बड़ी वजह ई-केवाईसी का अधूरा रहना है। सरकार साफ कर चुकी है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो इसे तुरंत पूरा कर लें। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की सुविधा दी है। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है, तो आप घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए आधिकारिक पोर्टल श्चद्वद्मद्बह्यड्डठ्ठ.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर 'ई-केवाईसी' विकल्प चुनें, आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी के जरिए सत्यापन पूरा करें।

ईरान छोड़िए, खाड़ी में असली खेल तो यूएई के साथ हो गया...यमन के बाद सोमालिया से भगाए गए अमीराती

दुबई, एजेंसी। यूएई की मुश्किल बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ पहले ही यूएई को यमन में नुकसान हुआ है। यमन में यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) को पीछे हटना पड़ा। इसी के बाद अब यूएई को सोमालिया में भी झटका लगा है। सोमालिया ने यूएई के साथ किए गए सभी समझौतों को खत्म कर दिया है। इनमें प्रमुख बंदरगाह संचालन, सुरक्षा सहयोग और रक्षा से जुड़े समझौते शामिल हैं। सोमालिया ने कहा कि यह फैसला उन हानिकारक कार्रवाइयों की वजह से लिया गया है, जो देश की एकता और संप्रभुता को कमजोर करती हैं।

सोमवार को मंत्रिपरिषद की ओर से इस फैसले की घोषणा के बाद, रक्षा मंत्री अहमद मुअल्लिम फिकी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह

कदम विश्वसनीय रिपोर्टों और सबूतों पर आधारित है। उनके मुताबिक, इन रिपोर्टों में यूएई से जुड़ी ऐसी गतिविधियों का जिक्र है, जो सोमालिया की संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाती हैं। फिलहाल, अभी इस पर यूएई का कोई कमेंट सामने नहीं आया है।

सोमालिया ने क्यों लिया फैसला?

स्वतंत्र सोमालिया विश्लेषक अब्दिनोर दाहिर के मुताबिक, सोमालिया का यह फैसला दिसंबर में इजराइल की ओर से सोमालिलैंड को मान्यता दिए जाने से जुड़ा हुआ लगता है। सोमालिलैंड, सोमालिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जिसने 1991 में खुद को अलग घोषित कर दिया था, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है।

दाहिर ने अल जजीरा से कहा, कई सोमाली मानते हैं कि यूएई ने इजराइल की ओर से सोमालिलैंड को मान्यता दिलाने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, इसी वजह से सोमाली कैबिनेट का यह फैसला [समझौते रद्द करने का] यूएई के खिलाफ एक जवाबी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यूएई पर अफ्रीका में गैर-सरकारी सशस्त्र समूहों और अलगाववादी ताकतों का समर्थन करने का आरोप लगाया जाता है, जिनमें सूडान की अर्धसैनिक आरएसएफ भी शामिल है। हालांकि, अबू धाबी लंबे समय से इन आरोपों से इनकार करता रहा है कि वो सूडान की सेना के खिलाफ युद्ध में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) को हथियार मुहैया करा रहा है।

UAE और सोमालिलैंड के रिश्ते

दिसंबर में यूएई ने सोमालिलैंड को इजराइल की ओर से मान्यता दिए जाने की निंदा करने वाले संयुक्त अरब-इस्लामिक बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन, 7 जनवरी को उसने अफ्रीकी संघ के साथ एक संयुक्त बयान जारी कर सोमालिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन का वादा किया। सोमालिया से अलग होने वाला सोमालिलैंड पिछले एक दशक में यूएई के लिए व्यापारिक और सुरक्षा निवेश का एक अहम केंद्र बनकर उभरा है। इसमें रणनीतिक बेरबेरा बंदरगाह पर यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड को दिया गया 30 साल का ठेका भी शामिल है।

यमन के बाद सोमालिया का एक्शन

सोमालिया का यह कदम उन रिपोर्टों के कुछ ही दिन बाद सामने आया है, जिनमें कहा गया था कि दक्षिणी यमन के अलगाववादी समूह साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के नेता ऐदारूस अल-जुबैदी 8 जनवरी को सोमालिलैंड के बेरबेरा बंदरगाह के जरिये यूएई पहुंचे थे। बताया गया कि उन्होंने रियाद में बातचीत के लिए सऊदी अरब के बुलावे को ठुकरा दिया था। इसके बाद सोमालिया की आव्रजन एजेंसी ने जांच शुरू करने का ऐलान किया। एजेंसी का कहना है कि सोमालिया के हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया।

ईरान ने अंतरराष्ट्रीय कॉल्स पर लगा प्रतिबंध हटाया लेकिन इंटरनेट बैन जारी, मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

तेहरान, एजेंसी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन ईरानी सरकार ने इस बीच एक अप्रत्याशित कदम उठाया है और अंतरराष्ट्रीय कॉल्स पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि इंटरनेट पर अभी भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है। एपी की रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को उनके विभिन्न कार्यालयों को ईरान से फोन आए। बताया गया कि ईरान के लोगों ने एपी के दुबई ब्यूरो को कॉल कर हालात की जानकारी दी। इससे पहले ईरान के लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इंटरनेट द्वारा ईरान का अभी भी दुनिया से संपर्क कटा हुआ है।

ईरान की सरकार का फैसला चौंकाने वाला

ईरान का यह फैसला बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि अभी भी ईरान में विरोध प्रदर्शन चरम पर हैं। 28 दिसंबर को शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शन में अभी तक 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (HRANA) के मुताबिक पूरे देश में फैले इस आंदोलन में कम से कम 646 लोगों की जान जा चुकी है और इस संख्या के और बढ़ने की आशंका है।

'मैं जो चाहे वो करूं, मेरी मर्जी', चीन ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, शेयर किया एआई वीडियो

बीजिंग। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके इस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। चीन ने इस घटना पर अमेरिका की आलोचना भी की थी। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर चीन ने मजाक उड़ाया है।

वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को उनकी बात मानने के लिए कहा। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद अब ग्रीनलैंड पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति की निगाहें टिकी हैं। इसके अलावा अमेरिका, ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर भी नजर बनाए हुए है और ईरानी सरकार पर हमला करने की धमकी भी दे चुका है। अमेरिका के ऐसे तेवर देखते हुए चीन की सरकारी मीडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक AI वीडियो शेयर किया

है, जिसका सीधा संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों से जोड़ा जा रहा है। चीन की सरकारी मीडिया के शेयर किए वीडियो में एक कैरेक्टर को अमेरिका के झंडे वाली टोपी पहने दिखाया गया है। इस वीडियो में कैप्शन के साथ बताया गया है कि ये कैरेक्टर लोगों से कह रहा है, 'तुम्हारा तेल, तुम्हारी जमीन, ये सब मेरा शिकार है।'

वीडियो के कैप्शन में यह भी लिखा है, 'मादुरो को हटाना, केवल एक छोटा सा खेल है। अंतरराष्ट्रीय नियम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और न ही मुझे किसी बात का मलाल है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है।' इस वीडियो में कैरेक्टर आगे कहता है, 'मैं जो चाहूं, वो करूं। मुझे जो कुछ चाहिए, वो मैं ले सकता हूं।' चीन की सरकारी मीडिया की तरफ से शेयर किए इस वीडियो के कैरेक्टर को डोनल्ड ट्रंप की नीतियों से जोड़ा गया है।

'ईरान में महिलाओं की स्वतंत्रता पर संकट', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई ने जताई चिंता

काबुल। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई ने मंगलवार को ईरान में महिलाओं की घटती स्वतंत्रता पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईरान में महिलाओं को लंबे समय से सार्वजनिक जीवन के लगभग हर पहलू से बाहर रखा गया है और ये पाबंदियां सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मलाला ने लिखा कि ईरान में जारी विरोध-प्रदर्शन दशकों से चली आ रही राज्य-प्रायोजित पाबंदियों से अलग नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि शिक्षा सहित सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की स्वायत्तता सीमित की गई है और ईरानी लड़कियां भी दुनिया भर की लड़कियों की तरह सम्मान और गरिमा से भरा जीवन चाहती हैं।

मलाला ने कहा कि ईरान के लोग वर्षों से इस दमन के खिलाफ चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को खामोश किया गया। उन्होंने इसे अलगाव, निगरानी और सजा पर आधारित एक व्यापक व्यवस्था का हिस्सा बताया, जो कक्षा से बाहर भी महिलाओं की स्वतंत्रता, पसंद और सुरक्षा को सीमित करती है। उन्होंने जोर दिया कि ईरानी महिलाओं को अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला स्वयं करने का अधिकार है और यह प्रक्रिया किसी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए।

ईरानी पत्रकार ने सरकारी कार्रवाई को उजागर किया

इस बीच, ईरानी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने विरोध-प्रदर्शनों पर कथित सरकारी कार्रवाई को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हज़ारों लोग मारे गए या घायल हुए हैं, इसके बावजूद ईरान के अलग-अलग शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर तानाशाही के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यही असली बहादुरी है।

मानवाधिकार संगठन और व्हाइट हाउस रख रहे नजर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के कई प्रांतों में बड़े प्रदर्शन हुए। इनमें अजरबैजान प्रांत और केंद्रीय शहर अराक शामिल हैं, जहां लोग झंडे लहराते और नारे लगाते दिखे। सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने भी प्रदर्शनों की पुष्टि की है। ये विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, आर्थिक संकट और शासन को लेकर जनता के गुस्से के बीच हो रहे हैं। मानवाधिकार संगठन के अनुसार, अब तक कम से कम 544 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,681 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हालात पर नजर रखी जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से निपटने के लिए सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं, जिनमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है, हालांकि उनकी प्राथमिकता कूटनीति बनी हुई है।

क्या विचाराधीन कैदी को वर्षों जेल में रखना सही? कोर्ट ने जीएसटी मामले में जमानत देकर कही ये बात

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि किसी विचाराधीन कैदी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए जीएसटी से जुड़े एक मामले में आरोपी अमित मेहरा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और अब तक मुकदमे की शुरुआत भी नहीं हो पाई है, ऐसे में लगातार कारावास न्यायसंगत नहीं है।

अमित मेहरा जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की ओर से दर्ज एक मामले में आरोपी हैं। उन पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने जमानत क्यों जरूरी मानी?

जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि अमित मेहरा आठ महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। अब तक न तो आरोप तय हुए हैं और न ही ट्रायल शुरू हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि मुकदमा जल्द शुरू भी हो जाए, तो उसके अगले एक साल में खत्म होने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में विचाराधीन कैदी को जेल में बनाए रखना अनुचित होगा।

अदालत ने किन बिंदुओं पर जोर दिया?

आरोपी आठ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है।

अभी तक मुकदमे की शुरुआत नहीं हुई है।

आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।

अधिकतम सजा पांच साल तक की है।

लंबे समय तक कैद व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है।

जमानत पर क्या शर्तें होंगी?

सुप्रीम कोर्ट ने अमित मेहरा को निचली अदालत द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के तहत जमानत देने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जीएसटी विभाग अपने हितों की सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शर्त चाहता है, तो वह निचली अदालत के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

फैसले का क्या है व्यापक संदेश?

शीर्ष अदालत के इस फैसले को विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अमित मेहरा की विशेष अनुमति याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया।

अदालत से UP के विधायक अब्बास अंसारी को राहत, गैंगस्टर एक्ट केस में अंतरिम जमानत अब नियमित हुई

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को अब पक्का (रेगुलर) कर दिया है। अब्बास अंसारी दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। यह मामला चित्रकूट जिले का है। वहां के कोतवाली कर्वी पुलिस स्टेशन में 31 अगस्त, 2024 को अब्बास अंसारी और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया था। इसी आधार पर उन पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अब्बास अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील निजाम पाशा ने दलीलें रखीं। कोर्ट ने इन दलीलों को सुना और पहले दी गई अंतरिम जमानत के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। मार्च 2025 में शीर्ष अदालत से मिली राहत ने अंसारी की कासगंज जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था। उन्हें उनके खिलाफ अन्य सभी आपराधिक मामलों में जमानत मिल गई थी। बेंच ने कुछ शर्तें लगाई थीं और बाद में उनमें से कुछ में ढील दी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच अधिकारी की अनुमति के बिना लखनऊ नहीं छोड़ सकते। अंसारी को चार नवंबर, 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था और छह सितंबर, 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मार्च में उन्हें राहत देते हुए, बेंच ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर एक्ट मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में जमानत मिल गई थी। बता दें की 18 दिसंबर, 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए पार्टी से हुए थे निष्कासित, अब नई पार्टी बनाएंगे मोहम्मद मुकीम

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा कांग्रेस से निष्कासित वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकीम ने नई पार्टी बनाने का एलान किया है। उन्होंने राज्य के युवाओं से एकजुट होने और ओडिशा के लोगों को नया राजनीतिक विकल्प देने की अपील की। मोहम्मद मुकीम ने सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मार्च तक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का एलान किया। इस कार्यक्रम में मोहम्मद मुकीम की बेटी और कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस भी शामिल हुईं। हालांकि इनके अलावा कोई प्रमुख राजनेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। मोहम्मद मुकीम ने कहा, नई पार्टी मौजूदा पार्टियों से अलग होगी और उनके दबदबे को चुनौती देगी। मुकीम ने कहा कि युवा शक्ति ही राज्य की राजनीति में बदलाव ला सकती है। मोहम्मद मुकीम ने दिसंबर में सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्तचरण दास और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना और मुकीम को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कार्यक्रम में शामिल होने वाली कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस से जब पूछा गया कि क्या वे कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पार्टी लाइन के खिलाफ गईं? तो सोफिया ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वे युवाओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुईं। हालांकि सोफिया ने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनके पिता की ये नई पहल सफल होगी। सोफिया फिरदौस ने कहा कि मैंने अपने पिता को लोगों के लिए काम करते हुए देखा है और उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। वहीं भक्तचरण दास ने मोहम्मद मुकीम के नई पार्टी बनाने के एलान पर तंज कसा। दास ने कहा जो लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे ईडी और आईटी से घबरा रहे हैं, वे भाजपा को खुश करने चले जाते हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस से नहीं जुड़ना चाहिए। बीजद सांसद देबाशीष समांत्रे ने कहा कि मोहम्मद मुकीम पूरे ओडिशा के नेता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोग कटक के बाहर मोहम्मद मुकीम को नहीं जानते तो फिर वे राज्य के नेता कैसे बन सकते हैं?

सामंथा की 'मां इंटी बंगारम' का टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में नजर आईं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर सामंथा रुथ प्रभु की नई फिल्म 'मां इंटी बंगारम' का टीजर आज रिलीज हो गया है। फिल्म को लेकर काफी दिनों से इंतजार था। अब आज टीजर देखने के बाद फैंस का उत्साह फिल्म के लिए और भी बढ़ गया है। टीजर में इमोशन से लेकर एक्शन तक देखने को मिल रहा है।

सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर बहुप्रतीक्षित टीजर साझा किया है। 1 मिनट 47 सेकंट के इस टीजर की शुरुआत में एक महिला (सामंथा) अपने पति के साथ ससुराल पहुंचती है। वह आत्मविश्वास से वादा करती है कि एक हफ्ते के भीतर वह उनका दिल जीत लेगी। एक आदर्श बहू बनने की कोशिश में वह एक पूरी तरह से कमीशन जांच शुरू कर देती है। हालांकि, वह अपने ससुराल वालों के सामने मासूम और शांत दिखती है। टीजर में सामंथा को एक दमदार एक्शन रोल में दिखाया गया है। उन्हें अकेले ही गुंडों को ढेर करते, भीषण गोलीबारी में शामिल होते और बाद में लाशों को ठिकाने लगाकर खून-खराबे को छिपाते हुए देखा जा सकता है। टीजर शेयर करते हुए सामंथा ने कैप्शन में लिखा, 'यह गोल्ड बेहद बोल्ड है।'

इस फिल्म का निर्माण सामंथा के पति राज निदिमोरु ने किया है। जबकि फिल्म का निर्देशन नंदिनी रेड्डी ने किया है। नंदिनी और सामंथा की जोड़ी ओह! बेबी के बाद दोबारा साथ में लौटी है। सामंथा के साथ फिल्म में गुलशन देवैया और दिगंथ मुख्य भूमिकाओं में हैं। जबकि दिग्गज अभिनेत्रियां गौतमी और मंजुषा अहम किरदारों में नजर आएंगी। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है।

टीजर दर्शकों को काफी पसंद आया है। कई यूजर्स ने सामंथा की बड़े पर्दे पर दमदार वापसी पर खुशी जताई है। एक फैन ने लिखा कि टीजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। जबकि एक ने लिखा की जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं कई प्रशंसकों ने सामंथा को एक्शन अवतार में देखकर खुशी जताई है। फैंस को सबसे ज्यादा बस में सामंथा का एक्शन सीन काफी पसंद आ रहा है, जहां वो साड़ी पहनकर जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं।

द राजा साब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 : दमदार ओपनिंग के बाद औंधे मुंह गिरी प्रभास की फिल्म

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डार्लिंग और ग्लोबल सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म द राजा साब ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल तो मचा दी, लेकिन दूसरे दिन के आंकड़ों ने निर्माताओं की को भी हैरान कर दिया है। पहले दिन दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से अधिक की ऐतिहासिक ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म को लेकर उम्मीद थी कि ये वीकेंड पर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, लेकिन इसका शनिवार का कारोबार बड़ी गिरावट लेकर आया।

प्रभास के प्रति फैंस की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज के पहले दिन सिनेमाघरों के बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। फैंस की भारी दीवानगी की बदौलत फिल्म ने 53 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली। हालांकि, शनिवार को इसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई और सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का कारोबार गिरकर महज 27 करोड़ रह गया। 2 दिनों में भारत में फिल्म की कुल कमाई 90.75 करोड़ हो गई है।

किसी भी बड़े बजट की फिल्म के लिए पहले 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी दौरान फिल्म अपनी लागत का बड़ा हिस्सा वसूलने की कोशिश करती है। द राजा साब ने पहले दिन शानदार ओपनिंग ली, लेकिन दूसरे दिन 48 प्रतिशत की गिरावट ने निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। फिल्म को हिट होने के लिए लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। बता दें कि द राजा साब करीब 400 करोड़ के भारी बजट में बनी है।

मारुति के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी प्रभास के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें विरासत में एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली मिलती है। यह हवेली उनके पूर्वजों की है, जिन्हें लोग राजा साब के नाम से जानते थे। फिल्म के विलेन संजय दत्त हैं। इसमें मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल भी हैं। निर्माताओं ने फिल्म के अंत में एक सरप्राइज देते हुए इसके दूसरे भाग की पुष्टि की है। दूसरे भाग का नाम होगा द राजा साबः सर्कस 1935।

ओ रोमियो से लेकर स्पिरिट तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में कई बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी आने वाले समय में कई शानदार फिल्मों में दिखाई देंगी। नया साल तृप्ति डिमरी के लिए काफी बिजी और खास होने वाला है, क्योंकि उनके पास बॉलीवुड से लेकर साउथ और ओटीटी प्रोजेक्ट्स तक लाइनअप तैयार है।

तृप्ति डिमरी ने साल 2017 में आई श्रेयर तलपड़े की 'पोस्टर बॉयज' से बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में वो सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं।

इसके बाद उन्हें 2018 की 'लैला मजनूं' में लीड रोल मिला, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस ने खूब तारीफें बटोरीं। फिर ओटीटी पर 'बुलबुल' (2020) और 'कला' (2022) से तृप्ति को क्रिटिकल फेम मिला।

वहीं, रणबीर कपूर के साथ एनिमल (2023) में उनकी भूमिका ने उन्हें बड़ी पॉपुलैरिटी दिलाई और उन्हें 'नेशनल क्रश' बना दिया। इसके बाद भूल भुलैया 3 (2024) और धड़क 2 (2025) जैसी फिल्मों से उनका करियर और मजबूत हुआ है। वहीं अब एक्ट्रेस कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आने वाली हैं। इनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई हैं।

बता दें, तृप्ति डिमरी शाहिद कपूर के साथ फिल्म ओ रोमियो में रोमांस करती नजर आएंगी। इस रोमांटिक फिल्म को विशाल भारद्वाज बना रहे हैं जो 13 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है।

वहीं, एनिमल के बाद तृप्ति डिमरी एक बार फिर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म का हिस्सा बन गई हैं। अपकमिंग फिल्म स्पिरिट में तृप्ति साउथ स्टार प्रभास के साथ नजर आने वाली हैं। फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है, हालांकि अभी रिलीज डेट से पर्दा नहीं उठा है।

रिपोर्ट्स की मानें तो तृप्ति डिमरी ओटीटी प्रोजेक्ट मां-बहन का भी हिस्सा हैं। इस फिल्म में तृप्ति डिमरी माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी। ये एक कॉमेडी-ड्रामा होगी जो साल 2026 में ही ओटीटी पर दस्तक दे सकती है।

इसके अलावा खबरें हैं कि, तृप्ति डिमरी लीजेंड्री एक्ट्रेस परवीन बाबी की बायोपिक में लीड रोल अदा करने वाली हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इसे नेटफ्लिक्स के लिए एक लिमिटेड एडिशन सीरीज के रूप में बनाया जा रहा है। इस सीरीज को शोनाली बोस डायरेक्ट कर रही हैं जिसकी शूटिंग मार्च 2026 में शुरू हो सकती है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com